RNI NO. PUNBIL/2014/59416

UTURNTIME.COM

यूटर्न टाइम

THE GOOD, BAD AND UGLY OF INDIA

FOLLOW US ON @UTURNTIMENEWS

जैस्मिन भसीन की गई याददाश्त

पेज 07

VOL: 03 | ISSUE 204 | MONDAY DATE 17-08-2026 | RS 3 | PAGE-8 | PUBLISHED BY: DELHI | HINDI DAILY NEWSPAPER Visit at : www.uturntime.com

संक्षिप्त खबरें

सुखबीर बादल अस्पताल से डिस्चार्ज, एनआईए से जांच की मांग

चंडीगढ़, यूटर्न/ 16 अगस्त । शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) प्रमुख और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उन्हें महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित गुरुद्वारे में हुए हमले के बाद भर्ती कराया गया था। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर हमलों की एनआईए जांच की मांग की है। उन्होंने हमले में इस्तेमाल 'किरपान' और घायल हाथ की तस्वीरें भी साझा कीं। बता दें कि सुखबीर बादल पर गुरुवार को नांदेड़ गुरुद्वारे में निहंग वेशधारी व्यक्ति ने हमला किया था। इससे पहले दिसंबर 2024 में अमृतसर स्वर्ण मंदिर के बाहर भी उन पर हमले की कोशिश हुई थी। हरसिमरत ने इसे बड़ी साजिश बताते हुए पंजाब पुलिस और आप सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 के हमले का आरोपी अब भी खुलेआम घूम रहा है और उसे आईएसआई से जुड़ा बताया।

पेपर लीक और सिवान गोलीकांड के खिलाफ 19 अगस्त को राजभवन मार्च करेंगे: तेजस्वी यादव

पटना, यूटर्न/ 16 अगस्त । राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में पेपर लीक, रोजगार और सिवान में छात्रों पर गोली चलाए जाने की घटना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इन मुद्दों को लेकर 19 अगस्त को राजभवन मार्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मार्च के माध्यम से राज्यपाल के समक्ष छात्रों और युवाओं की समस्याओं को रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार लगातार पेपर लीक की घटनाओं के कारण बदनाम हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में मैट्रिक, इंटर से लेकर विभिन्न बहाली परीक्षाओं तक में पेपर लीक की शिकायतें सामने आती रही हैं। उन्होंने कहा कि जब परीक्षाएं निष्पक्ष तरीके से नहीं होंगी तो मेहनत करने वाले छात्रों के साथ न्याय कैसे होगा। सिवान की घटना का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि छात्र अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे और वहां एके-47 से गोली चलाए जाने की घटना हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर पहले डीजीपी से भी मुलाकात की गई थी और सरकार से जिम्मेदारी तय करने की मांग की गई थी, लेकिन अब तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है।

तकनीक से तेज और पारदर्शी होगा शासन : सीएम रेखा गुप्ता

» नई दिल्ली, यूटर्न/ 16 अगस्त ।

दिल्ली सरकार राजधानी में आधुनिक ई-कैबिनेट प्रणाली लागू करेगी। इसी दिशा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) के विशेषज्ञों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक में ऐसी डिजिटल व्यवस्था पर विचार किया गया, जिसके माध्यम से दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठकों की पूरी प्रक्रिया कागज रहित (पेपरलेस), अधिक सुरक्षित, तेज और पारदर्शी बनाई जा सके।

सीएम रेखा गुप्ता का मानना है कि दिल्ली सरकार प्रशासनिक सुधारों और सुशासन के लिए आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। ई-कैबिनेट जैसी व्यवस्था लागू करने से कैबिनेट बैठकों से जुड़ी पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित की जा सकेगी। इससे निर्णय लेने की गति बढ़ेगी, गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षा मजबूत होगी और विभागों के बीच समन्वय भी अधिक प्रभावी बनेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में शासन-प्रशासन में तकनीक का प्रभावी उपयोग समय की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य ऐसी व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें सरकारी प्रक्रियाएं सरल हों, निर्णय तेजी से लिए जा सकें और उनके क्रियान्वयन की लगातार निगरानी भी संभव हो। ई-कैबिनेट प्रणाली के माध्यम से कैबिनेट बैठकों से जुड़े सभी दस्तावेज जैसे कैबिनेट नोट्स, बैठक का एजेंडा, उससे जुड़े संलग्न दस्तावेज (एनेक्सर), कैबिनेट के निर्णय और बैठक की कार्यवाही (मिनट्स), सुरक्षित डिजिटल माध्यम से तैयार, साझा और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाए जा सकेंगे। इससे कागजों पर निर्भरता लगभग समाप्त होगी और पूरी प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित एवं प्रभावी बनेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें प्रत्येक मंत्री और अधिकारी को उसकी जिम्मेदारी के अनुसार अलग-अलग स्तर की डिजिटल पहुंच दी जा सकती है। मंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, विभागीय सचिव जैसे सभी अधिकृत अधिकारी केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार संबंधित दस्तावेज देख सकेंगे। इससे गोपनीय जानकारी की सुरक्षा और अधिक मजबूत होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रस्तावित व्यवस्था में कैबिनेट नोट्स जमा करने, उनकी जांच करने, मंजूरी देने, संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने और भविष्य के लिए सुरक्षित रिकॉर्ड के रूप में संरक्षित करने जैसी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन संचालित की जा सकती है। इससे अनावश्यक देरी कम होगी और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट बैठकों के दौरान इस प्रणाली का सुरक्षित उपयोग टैबलेट के माध्यम से भी किया जा सकता है। इससे मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी बैठक के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेज तुरंत देख सकेंगे और निर्णय प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक होगी। इस प्रकार की व्यवस्था का एक बड़ा लाभ यह भी है कि कैबिनेट के किसी भी निर्णय के बाद संबंधित विभागों द्वारा उस पर की जा रही कार्रवाई की लगातार निगरानी की जा सकती है।

शाह ने अलवर में 6453 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण व शिलान्यास

» अलवर, यूटर्न/ 16 अगस्त ।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को राजस्थान के अलवर में किसान सम्मान निधि व फसल बीमा योजना के तहत किसानों को डीबीटी हस्तांतरण, 10,580 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरण और राजस्थान सरकार के 6,262 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा की महाभारत से काल से जिन्होंने पांडवों को आश्रय दिया, वो यही मत्य भूमि है। आज अटल जी की पूण्य तिथि है, आज ही अलवर मेडिकल कॉलेज का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से घोषित हो रहा है। अटल जी को देश का हर गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से याद करता रहेगा। पूरा देश उनको सुशासन के लिए भी याद करेगा।

अमित शाह ने कहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र निर्माण और अंत्योदय के लिए समर्पित कर दिया। आज राजस्थान के निम्बाहेड़ा में अटल जी की पुण्यतिथि पर उनकी 21 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। अटल जी ने सुशासन, विकास और राष्ट्रप्रथम की राजनीति की जो नींव रखी, उनकी यह प्रतिमा युवाओं को उन्हीं आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित करेगी।

एआई से परमाणु ऊर्जा तक, 2047 के भारत के लिए पीएम मोदी के बड़े ऐलान

» नई दिल्ली, यूटर्न/ 16 अगस्त ।

80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं, शिक्षा, खेल, नागरिक सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, परमाणु ऊर्जा और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई बड़े लक्ष्यों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए देश को तकनीक, ऊर्जा, कौशल और मानव संसाधन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ना होगा।

प्रधानमंत्री ने अगले एक वर्ष में एक करोड़ युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का प्रशिक्षण देने का ऐलान किया। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क विकसित करने की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यमवर्गीय परिवारों पर महंगी कोचिंग का बोझ कम करना है।

खेल क्षेत्र में 5 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए देशव्यापी प्रतिभा खोज अभियान शुरू करने की घोषणा हुई। चुनी गई प्रतिभाओं को विशेष प्रशिक्षण देकर अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे।

तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए प्रधानमंत्रीने बताया कि तीन सेमीकंडक्टर संयंत्र शुरू हो चुके हैं और इनके उत्पादों का निर्यात भी शुरू हो गया है। अगले 7-8 वर्षों में 5 से 8 नए सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इस दशक में पांच नए परमाणु रिएक्टर शुरू करने की योजना है।

अटल पुण्यतिथि पर संकल्प पूरा, दिल्ली में 100 अटल कैंटीन का लक्ष्य हासिल

25 नई कैंटीनों का किया उद्घाटन, रोजाना 1 लाख लोगों को मिलेगा खाना

नई दिल्ली, यूटर्न/ 16 अगस्त । भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर दिल्ली सरकार ने अपने प्रमुख संकल्पों में से एक को पूरा कर लिया है। 25 दिसंबर 2025 को अटल जी की 100वीं जयंती पर शुरू किए गए 100 'अटल कैंटीन' के लक्ष्य को मात्र आठ महीनों के भीतर हासिल कर लिया गया। रविवार को पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी, शहरी विकास मंत्री आशीष सूद और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन से 25 नई अटल कैंटीन का आधिकारिक उद्घाटन किया। अटल कैंटीन के माध्यम से जरूरतमंदों, मजदूरों, प्रवासियों और झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले लोगों को मात्र 5 में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि अब विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन (गेट नंबर-3) के पास कैंटीन खुलने से दूर-दराज से आकर हॉस्टलों और पीजी में रहने वाले छात्रों को भी सस्ता और गुणवत्तापूर्ण खाना मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि यह योजना अटल जी के 'अंत्योदय' और जनसेवा के आदर्शों को समर्पित एक सच्ची श्रद्धांजलि है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा संचालित इन 100 कैंटीनों के जरिए प्रतिदिन लगभग 1 लाख लोगों को भोजन कराया जाएगा।

देशवासियों को प्रेरणा देता है वीरांगनाओं का त्याग और बलिदान, रानी अवंती बाई महान क्रांतिकारी : योगी

» लखनऊ, यूटर्न/ 16 अगस्त ।

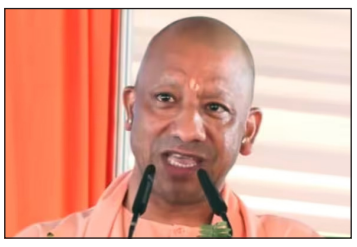

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम ने उन्हें भारत की आजादी के प्रथम स्वातंत्र्य समर 1857 की महान क्रांतिकारियों में से एक बताया और कहा कि वीरांगनाओं का योगदान, तप, त्याग और बलिदान हम सभी को प्रेरणा देता है।

सीएम योगी ने कहा कि आज उनकी 196वीं जयंती है। वर्ष 1857 में वे मात्र 27 वर्ष की थीं। इस छोटी आयु में उन्होंने आजादी के संघर्ष में बलिदान कर मिसाल प्रस्तुत की। आजादी के लिए उनका बलिदान युवाओं के लिए प्रेरणा है। वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी भारत की आजादी की उन महान नायिकाओं में से एक हैं, जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने आजादी के लिए सर्वस्व न्योछावर करने में कोई कोताही नहीं बरती। वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ देश की आजादी के लिए युद्ध को लड़ा गया, हर व्यक्ति आज भी बड़ी श्रद्धा से उनकी स्मृतियों को नमन करता है। उनके योगदान के लिए हर भारतवासी नतमस्तक है। सीएम योगी ने कहा कि वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी का आदर्श उत्तर प्रदेश के लिए प्रेरणा बन सके, इसके लिए हमारी सरकार ने यूपीपीएसी की तीन नई महिला बटालियन के गठन के कार्य को बढ़ाया और इनका नामकरण/गठन इन्हीं वीरांगनाओं के नाम पर किया। बदायूं में रानी अवंती बाई लोधी के नाम पर पीएसी की नई वाहिनी का गठन किया।

मुफ्त बस यात्रा: दिल्ली सरकार 31 अगस्त तक महिलाओं के लिए 'पिंक टिकट' का इस्तेमाल बंद करेगी

» नई दिल्ली, यूटर्न/ 16 अगस्त ।

महिला यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और परिवहन विभाग (क्लस्टर) की बसों में मुफ्त यात्रा के लिए मौजूदा कागज आधारित 'पिंक टिकट' की व्यवस्था को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने रविवार को यह जानकारी दी।

मंत्री ने आगे बताया कि 1 सितंबर से मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय त्योहारों और रक्षा बंधन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि त्योहारों के दौरान बढ़ी हुई यात्रा के दौरान महिला यात्री बिना किसी असुविधा के यात्रा कर सकें।

उन्होंने यह भी कहा कि इस विस्तार से पात्र महिलाओं को अपना पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए अतिरिक्त समय भी मिलेगा।

मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि त्योहारी मौसम, विशेषकर रक्षा बंधन, ऐसे अवसर होते हैं जब हमारी माताएं, बहनें और बेटियां अपने परिवारों से मिलने के लिए यात्रा करती हैं। उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने मौजूदा व्यवस्था को 31 अगस्त तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। मंत्री ने आगे कहा कि हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि इस बदलाव के दौरान किसी भी पात्र महिला यात्री को कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि संशोधित व्यवस्था के अनुसार, पात्र महिला यात्री 31 अगस्त तक पेपर-आधारित गुलाबी टिकट प्राप्त करना जारी रख सकती हैं और डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकती हैं। 1 सितंबर से, मुफ्त यात्रा केवल वैध पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के माध्यम से ही उपलब्ध होगी। मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि अब तक 18,13,866 पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग ने डिपो प्रबंधकों, क्षेत्रीय प्रबंधकों, कंडक्टरों और प्रवर्तन कर्मचारियों को संशोधित समय सीमा का व्यापक प्रचार करने और महिला यात्रियों को 31 अगस्त से पहले अपने कार्ड प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया है।

उन्होंने आगे कहा कि डिपो और बसों में घोषणाओं, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और अन्य माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार सार्वजनिक परिवहन को सुलभ, सुविधाजनक और प्रौद्योगिकी-आधारित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सभी पात्र महिला यात्रियों से अपील करते हैं कि वे 31 अगस्त से पहले अपना पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवा लें और 1 सितंबर, 2026 से निर्बाध रूप से मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ उठाना जारी रखें।

'वंदे मातरम' प्रकरण में हिंदू सेना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से की शिकायत, निष्पक्ष जांच की मांग

» नई दिल्ली, यूटर्न/ 16 अगस्त ।

कांग्रेस मुख्यालय में 15 अगस्त को 'वंदे मातरम' के पूर्ण गायन के दौरान सामने आए एक वीडियो को लेकर हिंदू सेना ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से शिकायत की है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने ईमेल के जरिए शिकायत भेजकर मामले की निष्पक्ष और तथ्यात्मक जांच की मांग की है। शिकायत में विष्णु गुप्ता ने कहा है कि 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 'वंदे मातरम' का पूर्ण गायन किया जा रहा था। इसी दौरान कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी द्वारा किए गए कुछ इशारों का एक वीडियो सामने आया, जिसके बाद इस घटना को लेकर चर्चा और विवाद शुरू हुआ। हिंदू सेना की ओर से पुलिस आयुक्त को भेजी गई शिकायत में कहा गया है कि विभिन्न समाचार माध्यमों में इस घटना से संबंधित खबरें प्रकाशित हुई हैं और कुछ मीडिया रिपोर्टों में आरोप लगाया गया है कि 'वंदे मातरम' के पूर्ण गायन के दौरान सोनिया गांधी के इशारों से राष्ट्रगीत का अपमान हुआ। हालांकि, शिकायत में इन आरोपों को निष्कर्ष के तौर पर पेश करने के बजाय पूरे मामले की जांच की मांग की गई है। विष्णु गुप्ता ने कहा कि वायरल वीडियो की वास्तविकता और उसके पूरे संदर्भ की जांच की जानी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कार्यक्रम के दौरान वास्तव में क्या हुआ था। शिकायतकर्ता ने पुलिस से 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम की मूल और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित कराने, उपलब्ध ऑडियो-वीडियो फुटेज की जांच करने और कार्यक्रम से जुड़े अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का अनुरोध किया है। इसके अलावा कार्यक्रम में मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों और संबंधित लोगों के बयान दर्ज करने तथा सोनिया गांधी द्वारा किए गए कथित इशारों के वास्तविक उद्देश्य और परिस्थितियों की भी जांच करने की मांग की गई है। शिकायत में कहा गया है कि यदि जांच में यह प्रमाणित होता है कि जानबूझकर 'वंदे मातरम' के गायन को रोकने, उसमें बाधा डालने या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का कोई कृत्य किया गया है, तो लागू कानून के तहत उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। विष्णु गुप्ता ने पुलिस से शिकायत पर की गई कार्रवाई और जांच के परिणाम से उन्हें अवगत कराने का भी अनुरोध किया है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि यह कदम किसी राजनीतिक द्वेष या व्यक्तिगत दुर्भावना के कारण नहीं उठाया गया है, बल्कि 'वंदे मातरम' की गरिमा, राष्ट्रीय भावनाओं के सम्मान और कानून के शासन को बनाए रखने के उद्देश्य से शिकायत की गई है।

ग्रामीण भारत में बढ़ रहा मधुमेह का बोझ, इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना जरूरी: डॉ. जितेंद्र सिंह

» नई दिल्ली, यूटर्न/ 16 अगस्त ।

केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने रविवार को मधुमेह की रोकथाम को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने का आ'ान किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत अब मधुमेह महामारी से अछूता नहीं है और इसके लिए समुदाय-आधारित, प्रौद्योगिकी-सक्षम और डेटा-आधारित प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया (आरएसएसडीआई) के ग्रामीण मधुमेह आउटरीच डिजिटल पोर्टल के उद्घाटन और मधुमेह जागरूकता वीडियो लाइब्रेरी 'विश्वास' के शुभारंभ के अवसर पर बोलते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि मधुमेह और इसकी जटिलताओं के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए रोकथाम, शीघ्र पहचान, समय पर हस्तक्षेप और निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई आवश्यक हैं।

उन्होंने कहा कि भारत की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी 40 वर्ष से कम आयु की है, इसलिए देश की युवा आबादी के स्वास्थ्य और उत्पादक क्षमता की रक्षा करना 'इंडिया-2047' के विजन के लिए आवश्यक है।

डॉ. सिंह ने कहा कि भारत ने स्वास्थ्य सेवा, वैज्ञानिक अनुसंधान और डिजिटल नवाचार में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन अगली चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि ये प्रगति ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों के लोगों तक पहुंचे।

मंत्री ने कहा कि ग्रामीण भारत अब मधुमेह की महामारी से अछूता नहीं है और इस बीमारी और इसकी जटिलताओं के बोझ को कम करने के लिए शीघ्र निदान, समय पर हस्तक्षेप, जीवनशैली में बदलाव और निरंतर निगरानी आवश्यक हैं।

उन्होंने कहा कि आरएसएसडीआई ग्रामीण आउटरीच कार्यक्रम इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कैसे पेशेवर चिकित्सा संगठन विशेषज्ञता को समुदायों के करीब लाकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रयासों को पूरक बना सकते हैं।

इस पहल के तहत, मधुमेह जागरूकता, स्क्रीनिंग, उपचार और दीर्घकालिक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक संरचित प्रणाली बनाने हेतु गांवों को गोद लिया जा रहा है।

यह कार्यक्रम पहले ही कई राज्यों के लगभग 30 गांवों तक पहुंच चुका है, और आने वाले वर्षों में इसके विस्तार की योजना है। मंत्री ने कहा कि नव-उद्घाटित डिजिटल पोर्टल व्यवस्थित दस्तावेजीकरण, रोगी देखभाल की निरंतरता, परिणामों की निगरानी और भविष्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियों के लिए साक्ष्य जुटाने में सक्षम बनाकर सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करेगा।

भारत को 2047 तक विकसित बनाने के लिए 10 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी का लक्ष्य रखना जरूरी : रिपोर्ट

नई दिल्ली, यूटर्न/ 16 अगस्त । अगर देश को 'विकसित भारत 2047' के विजन को सही मायने में साकार करना है, तो देश को अपनी अर्थव्यवस्था के आकार में काफी विस्तार करना होगा और अर्थव्यवस्था को कम से कम 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना जरूरी होगा। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई।

पूर्व राजनयिक मोहन कुमार ने 'द जेरूसलम पोस्ट' में प्रकाशित एक आर्टिकल में कहा कि भारत के जीडीपी के लिहाज से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर गर्व किया जा सकता है, लेकिन देश की विशाल आबादी को देखते हुए वर्तमान आर्थिक आकार अभी भी पर्याप्त नहीं है। उन्होंने लिखा, 'इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत दुनिया में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लिहाज से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने पर गर्व कर सकता है, लेकिन करीब 1.5 अरब की आबादी वाले देश के लिए 4.5 ट्रिलियन डॉलर की मौजूदा जीडीपी अपेक्षाकृत कम है।' आर्टिकल के अनुसार, भारत वैश्विक विदेशी व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर, अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करके और गहरे एवं संरचनात्मक आर्थिक सुधार लागू करके 10 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है।

दिल्ली: कर्मजीवी आवास योजना के तहत पहले दिन ही डीडीए के 1,218 फ्लैटों में से आधे बिके

» नई दिल्ली, यूटर्न/ 16 अगस्त

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की कर्मजीवी आवास योजना 2026 को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। योजना के तहत पेश किए गए 1,218 फ्लैटों में से 50 प्रतिशत से अधिक फ्लैट पहले ही दिन बिक गए। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। इसमें 1-बीएचके फ्लैट की मांग सबसे अधिक रही और उपलब्ध सारी यूनिट बिक चुकी हैं।

उपराज्यपाल और डीडीए के अध्यक्ष टी.एस. संधू के मार्गदर्शन में शुरू की गई इस योजना के तहत पहले दिन ही 1,218 में से 661 फ्लैटों की बुकिंग हो गई।

अधिकारी ने एक बयान में कहा कि यह मजबूत प्रतिक्रिया नरेला में डीडीए के आवासों की बढ़ती मांग और किफायती, तुरंत रहने योग्य घर उपलब्ध कराने की डीडीए की पहल पर खरीदारों के भरोसे को दर्शाती है।

इस योजना के तहत बुकिंग रविवार को 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 'पहले आओ, पहले पाओ' (एफसीएफएस) आधार पर शुरू हुई।

डीडीए ने कहा, '1-बीएचके श्रेणी में प्रतिक्रिया विशेष रूप से जबरदस्त रही, जो घर खरीदारों और कामकाजी पेशेवरों के बीच किफायती आवास की मजबूत मांग को दर्शाती है।'

यह शानदार प्रतिक्रिया पिछले कुछ महीनों में नरेला में डीडीए की मजबूत आवास बिक्री के बाद आई है और इससे यह भी पता चलता है कि नरेला सब-सिटी एक पसंदीदा आवासीय गंतव्य के रूप में उभर रही है।

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में डीडीए ने 1,284 फ्लैट बेचे, जिससे 1,020 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ।

इनमें अकेले नरेला में 1,153 फ्लैट बिके, जो कुल बिक्री का लगभग 90 प्रतिशत है।

बयान में कहा गया कि कर्मजीवी आवास योजना 2026 का उद्देश्य कामकाजी पेशेवरों के लिए घर का मालिक बनना अधिक किफायती और आसान बनाना है। साथ ही, यह राष्ट्रीय राजधानी में सुनियोजित और समावेशी शहरी विकास के प्रति डीडीए की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाती है।

योजना के तहत डीडीए ने नरेला के सेक्टर ए1-ए4 के पॉकेट-11 में 1,218 तैयार फ्लैटों की पेशकश की है। इन फ्लैटों पर सीधे 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। योजना में 1-बीएचके, 2-बीएचके और 3-बीएचके फ्लैट शामिल हैं। छूट के बाद 1-बीएचके फ्लैट की कीमत 33.40 लाख रुपए, 2-बीएचके की कीमत 75.55 लाख रुपए और 3-बीएचके की कीमत 1.065 करोड़ रुपए से शुरू होती है।

यह योजना विशेष रूप से सेवारत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ कॉरपोरेट, व्यवसाय, उद्यमिता और पेशेवर क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए तैयार की गई है। इसके तहत उन्हें दिल्ली में तुरंत रहने योग्य घर खरीदने का आकर्षक अवसर दिया जा रहा है।

उत्तराखंड के हल्द्वानी में दलित समाज के अपमान के खिलाफ किया प्रदर्शन , घटना दुर्भाग्यपूर्ण

दलित समाज ने गंगाजल और हवन से शुद्धिकरण किए जाने की घटना की कड़े शब्दों में निंदा : डॉ ओमवीर सिंह पंवार

» निर्मल सिंह विर्क

पानीपत, यूटर्न/ 16 अगस्त । उत्तराखंड के हल्द्वानी में दलित समाज से आने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिस मंच से देश को संबोधित कर चुके हैं, उस स्थान पर भाजपा-आरएसएस से जुड़े लोगों द्वारा कथित रूप से गंगाजल और हवन के माध्यम से शुद्धिकरण किए जाने की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय और सामाजिक सद्भाव पर चोट करने वाली है।

इस घटना के विरोध में पानीपत लघु सचिवालय के सामने कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथियों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया।

मैंने भी अपने साथियों के साथ इस

विरोध-प्रदर्शन में बढ़-चढ़कर सहभागिता करते हुए ऐसी संकीर्ण और जातिवादी मानसिकता के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति के सम्मान की नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान, समानता और संविधान के मूल्यों की लड़ाई है। भाजपा और आरएसएस के उन लोगों को समझना होगा कि भारत का संविधान किसी की जाति देखकर सम्मान देना या अपमान करना नहीं सिखाता। बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने जिस समानता और सामाजिक न्याय के भारत का सपना देखा था, उसे किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने दिया जाएगा।

जो लोग समाज को जाति और धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति करते हैं, उन्हें देश की जनता करारा जवाब देगी।

पूज्य ज्ञानेश्वरदास स्वामी के सान्निध्य में कुरुक्षेत्र में हुआ विशेष सत्संग

» अश्विनी वालिया

कुरुक्षेत्र, यूटर्न/ 16 अगस्त। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र स्थित बी ए पी एस स्वामिनारायण अक्षरधाम मंदिर में 15 अगस्त को विशेष सत्संग का आयोजन श्रद्धा एवं आध्यात्मिक वातावरण में किया गया। कार्यक्रम मे बी ए पी एस सारंगपुर मंदिर के मुख्य कार्यकारी संत पूज्य ज्ञानेश्वरदास स्वामी के सान्निध्य में बड़ी संख्या में हरि भक्तों ने सत्संग का लाभ लिया और संत के दर्शन कर आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया। सत्संग के दौरान पूज्य ज्ञानेश्वरदास स्वामी ने श्रद्धालुओं को भक्ति, संस्कार, सेवा, सदाचार और आध्यात्मिक जीवन के महत्व के बारे में प्रेरणादायी मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिकता और अच्छे संस्कारों का विशेष महत्व है तथा परिवार और समाज में सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए सेवा, सद्भाव और भक्ति की भावना

को मजबूत करना आवश्यक है। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने भजन, प्रार्थना एवं सत्संग में सहभागिता की। मंदिर परिसर में पूरे कार्यक्रम के दौरान भक्तिमय वातावरण बना रहा।

हरि भक्तों ने पूज्य संत के दर्शन एवं आशीर्वचन प्राप्त कर स्वयं को धन्य महसूस किया। इस अवसर बी ए पी एस स्वामिनारायण संस्था से जुड़े संतों एवं स्वयंसेवकों ने कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से संभाला।

उर्वरक विभाग में बेहतरनी कार्य करूंगा : अशोक कनौजिया

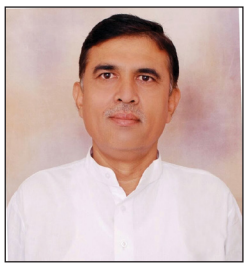

हरियाणा, यूटर्न/ 16 अगस्त । भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक कनौजिया को भारत सरकार ने उर्वरक विभाग में स्वतन्त्र डायरेक्टर बनाया गया है। जिस पर अशोक कनौजिया ने प्रसन्नता प्रकट की है व केन्द्रीय नेतृत्व को विश्वास दिलाया है कि उन्हें जो जिम्मेवारी मिली है वह उन्हें पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं कर्तव्य परायणता से निभायेंगे। अशोक कनौजिया ने बताया कि केन्द्र सरकार में उनके मन्त्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी होंगे व उन्हें आगामी कम से कम 3 साल के लिये यह जिम्मेवारी दी है। कनौजिया ने अपनी नियुक्ति पर हरियाणा की समस्त भारतीय जनता पार्टी के संगठन एवं हरियाणा के मुख्यमन्त्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया है। कनौजिया ने कहा कि देश में केवल भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती है। अशोक कनौजिया ने विश्वास प्रकट किया है कि वह अपने कार्यो से रसायन एवं उर्वरक मन्त्रालय में अपनी कार्यशैली से ज्यादा से ज्यादा जनता का भला करने का काम करेंगे।

एसआरएमआईएसटी के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति बोले-'विकसित भारत में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका'

» चेन्नई, यूटर्न/ 16 अगस्त ।

भारत के उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने रविवार को चेन्नई के पास चेंगलपट्टू के कट्टनकुलथुर में स्थित एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (एसआरएमआईएसटी) के 22वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने स्नातक छात्रों से 'राष्ट्र प्रथम' के सिद्धांत से प्रेरित होकर राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का उपयोग करने का आ'ान किया।

उपराष्ट्रपति ने स्नातक छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह मात्र उपाधि प्रदान करने से कहीं अधिक है। यह वर्षों की लगन, अनुशासन और ज्ञान का उत्सव है, साथ ही यह जीवन भर की जिम्मेदारी और सेवा की यात्रा की शुरूआत का प्रतीक भी है।

सीपी राधाकृष्णन ने अंतरविषयक शिक्षा, रचनात्मकता, उद्यमिता और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाले शैक्षणिक वातावरण के निर्माण के लिए एसआरएमआईएसटी की सराहना की। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर अनुसंधान, रोबोटिक्स, जैव प्रौद्योगिकी और सतत विकास पर संस्थान के बढ़ते ध्यान का उल्लेख करते हुए कहा कि ये क्षेत्र भविष्य की अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को रूप देंगे। उपराष्ट्रपति ने जीवन में सुधार लाने वाले, उद्योग मजबूत करने वाले और सतत विकास में योगदान देने वाले

अनुसंधान को व्यावहारिक समाधानों में बदलने पर एसआरएमआईएसटी की सराहना की। उन्होंने कहा कि अनुसंधान तभी अपने सर्वोच्च उद्देश्य को प्राप्त करता है जब वह समाज की सेवा करता है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि अनुसंधान तभी सही मायने में सराहनीय होता है जब वह सही परिणाम देता है, समाज पर सार्थक प्रभाव डालता है और उससे लोगों को व्यावहारिक लाभ होता है।

उपराष्ट्रपति ने कोविड-19 महामारी के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को याद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 100 से अधिक देशों को कोविड-19 टीके उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि भारत ने मानवीय सहायता का व्यवसायीकरण करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने हाल ही में केन्या के स्पीकर जिन्होंने भारत की वैक्सीन सहायता के लिए आभार व्यक्त किया था, उनके साथ हुई बातचीत को याद करते हुए कहा कि कई पश्चिमी देशों ने गरीब देशों को इस तरह की सहायता प्रदान नहीं की। उन्होंने आगे कहा कि भारत के प्रयासों ने मानवता की रक्षा में मदद की और दोहराया कि भारत शांति, विकास और मानवता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था कि एम्स पूरे देश में होने चाहिए ताकि चिकित्सा सुविधाएं और चिकित्सा शिक्षा पूरे भारत के लोगों तक पहुंच सके। उपराष्ट्रपति ने 2014 से देश में उच्च शिक्षा के विस्तार के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान 16 आईआईआईटी, 8 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 8 आईआईएम, 7 आईआईटी, 2 आईआईएसईआर, 1 एनआईटी और 12 एम्स स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत में 1,425 से अधिक विश्वविद्यालय, 54,000 कॉलेज और 16,850 स्वतंत्र संस्थान हैं। सी. पी. राधाकृष्णन ने उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में हुई उल्लेखनीय वृद्धि के बारे में भी बताया। यह 2014-15 में 1.57 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 2.24 करोड़ हो गई, यानी इसमें 42.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोहों में डिग्री और पदक प्राप्त करने वाली महिलाओं की बढ़ती संख्या एक स्वागत योग्य कदम है। सी. पी. राधाकृष्णन ने कहा कि स्नातक भारत के विकसित भारत 2047 की यात्रा में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहे हैं।

80वें स्वतंत्रता दिवस के रंग में रंगा ओ.एस.जी.यू व ओ.आई.पी.एस

» राजेश सलूजा

हरियाणा, यूटर्न/ 16 अगस्त । ओम स्टर्लिंग ग्लोबल विश्वविद्यालय एवं ओम इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के सौजन्य से 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह अत्यंत हर्षोल्लास और गर्व के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के चांसलर डॉ. पुनीत गोयल एवं प्रो-चांसलर डॉ. पूनम गोयल ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

समारोह की शुरूआत ओम स्टर्लिंग ग्लोबल विश्वविद्यालय के ग्रुप सीओओ एंड प्रोवोस्ट डॉ अजय कुमार पोद्दार व विश्वविद्यालय कुलपति महोदय डॉ एन. पी. कौशिक द्वारा ध्वजारोहण एवं परेड की सलामी के साथ हुई।

उन्होंने ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि आज का दिन हमें यह संकल्प लेने का अवसर देता है कि हम जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर एक सशक्त, शिक्षित और विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। इसके उपरांत ओम इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक

कार्यक्रमों ने दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में देशभक्ति पर आधारित नृत्य, नाटिका और समूहगान की प्रस्तुतियों ने देशप्रेम की भावना को प्रबल किया। कार्य्रकम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुति देने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।

साथ ही उन्हें विधालय एवं विश्वविद्यालय के नियमों और अनुशासन का पालन करने की शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर ओ. आई.पी.एस. के प्रधानाचार्य श्री के. एल. गोस्वामी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए बलिदान का हमें सदैव सम्मान करना चाहिए और उनके बताए हुए मार्गदर्शन को अपने जीवन में अपनाना भी चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के इस रंगारंग कार्यक्रम में डॉ सुमेश जैन, डॉ शोभना पोद्दार, डॉ राजेश नांदल सहित विश्वविद्यालय एवं ओ.आई.पी.एस. के सभी शिक्षक, विद्यार्थी उपस्थित रहे। देश भक्ति गीतों के साथ विश्वविद्यालय प्रांगण गूंज उठा।

ध्वजारोहण, तिरंगा यात्रा और प्रतिभाओं का सम्मान बना आकर्षण का केंद्र

हरियाणा, यूटर्न/ 16 अगस्त । स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर ओआरसी सैनिक अकादमी, ढकोली में देशभक्ति, अनुशासन और उत्साह से ओत-प्रोत भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कर्नल एस.एस. चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर अकादमी के निदेशक रंजीत रंजन झा, रिचा झा, समस्त फैकल्टी सदस्य एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ पूरे सम्मान एवं गरिमा के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर किया गया। जैसे ही तिरंगा आसमान में लहराया, पूरा परिसर राष्ट्रभक्ति के नारों और देशभक्ति की भावना से गूंज उठा। विद्यार्थियों ने अनुशासन एवं एकता का परिचय देते हुए भव्य तिरंगा यात्रा निकाली, जिसने क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को विशेष बना दिया। समारोह का प्रमुख आकर्षण जीके क्विज प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों का पुरस्कार वितरण समारोह रहा।

हरियाणा में 2022 से 2026 तक नियुक्त नए कर्मचारियों का तबादला क्यों नहीं?

संदीप शर्मा

नियुक्ति पत्र में अगली ऑनलाइन प्रक्रिया में भाग लेना अनिवार्य, तो मौजूदा अभियान से बाहर क्यों? हरियाणा सरकार की ऑनलाइन तबादला नीति का उद्देश्य कर्मचारियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और समान अवसर पर आधारित बनाना है। ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने का मकसद यही था कि तबादलों में व्यक्तिगत पसंद-नापसंद या मनमाने प्रशासनिक फैसलों की गुंजाइश कम हो और योग्य कर्मचारियों को निर्धारित नियमों के तहत अपनी पसंद के स्थान के लिए आवेदन करने का समान अवसर मिले। हालांकि, किसी भी नीति की प्रभावशीलता उसके बनाए जाने से नहीं, बल्कि उसके निष्पक्ष और एकरूप तरीके से लागू होने से तय होती है। इसी कड़ी में वर्ष 2022 से 2026 के बीच नियुक्त हुए कर्मचारियों को वर्तमान ऑनलाइन तबादला अभियान से बाहर रखने का मामला कई सवाल खड़े करता है। यदि नियुक्ति पत्र में इन कर्मचारियों को भविष्य की ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया में भाग लेने की स्पष्ट शर्त दी गई थी, तो फिर मौजूदा अभियान में उन्हें शामिल न किए जाने का आधार क्या है? यह विषय कर्मचारियों के हित और तबादला नीति की पारदर्शिता के लिहाज से गंभीरता से विचार किए जाने की मांग करता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब इस अवधि में नियुक्त सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया में भाग लेना पड़ रहा है, तो अन्य विभागों के समान अवधि में नियुक्त कर्मचारियों को इससे पीछे क्यों रखा जा रहा है? यदि शिक्षकों को नीति के तहत अनिवार्य भागीदारी के दायरे में लाया जा सकता है, तो समान अवधि में नियुक्त अन्य पात्र कर्मचारियों के लिए अलग व्यवस्था का स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ और तर्कसंगत आधार भी होना चाहिए। यहां मांग किसी कर्मचारी को उसकी पसंद के स्थान पर तबादला देने की नहीं, बल्कि पात्र होने पर प्रक्रिया में भाग लेने, विकल्प देने और नियमों के अनुसार विचार किए जाने के समान अवसर की है। इस विषय में 23 मई 2025 की कट-ऑफ तिथि, 'नोशनल श्रेणी' और 2026 की मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति में प्रयुक्त 'प्रत्येक कैडर का पहला ऑनलाइन तबादला अभियान' जैसे प्रावधान महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन प्रावधानों को समझने के लिए संबंधित कैडर का वास्तविक प्रशासनिक इतिहास देखना आवश्यक है। यदि किसी कैडर में 2026 में पहली बार ऑनलाइन तबादला अभियान हो रहा है, तो उसकी स्थिति उस कैडर से अलग हो सकती है जिसमें 2017 से ऑनलाइन तबादला अभियान होते रहे हैं। इसलिए एक ही कट-ऑफ को सभी कैडरों पर यांत्रिक रूप से लागू करने से पहले उनके वास्तविक नीतिगत इतिहास को देखना आवश्यक है।

समानता का प्रश्न केवल शिक्षकों और अन्य विभागों तक सीमित नहीं है। कुछ विभागों में ऑनलाइन तबादला नीति लागू होने और ऑनलाइन अभियान आयोजित किए जाने के बावजूद कर्मचारियों को ऑफलाइन स्टेशन आवंटित किए जाने की स्थिति भी गंभीर विचार की मांग करती है। हरियाणा के पशुपालन विभाग का उदाहरण इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। विभाग में 2020 से वीएलडीए कैडर के लिए ऑनलाइन तबादला नीति लागू है और इसके अंतर्गत दो ऑनलाइन तबादला अभियान भी हो चुके हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार, 2020 के बाद नियुक्त वीएलडीए कैडर के लगभग 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ऑफलाइन स्टेशन आवंटित किए गए। यदि यह आंकड़ा विभागीय अभिलेखों से पुष्ट होता है, तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ऑनलाइन तबादला नीति और उसके अंतर्गत अभियान पहले से लागू होने के बावजूद इतने बड़े स्तर पर ऑफलाइन स्टेशन आवंटित करने का आधार क्या था। प्रश्न इससे भी गंभीर तब बनता है जब ऐसे कर्मचारियों के नियुक्ति पत्र अथवा स्टेशन आवंटन संबंधी दस्तावेजों में यह शर्त दर्ज रही हो कि उन्हें अगले ऑनलाइन तबादला अभियान में अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा। यदि कर्मचारी को ऑफलाइन स्टेशन देते समय सरकार ने स्वयं यह शर्त रखी कि अगली ऑनलाइन प्रक्रिया में उसे भाग लेना होगा, तो बाद में किसी नई व्याख्या या आदेश के आधार पर उसी कर्मचारी को ऑनलाइन अभियान से बाहर करना प्रशासनिक न्याय और वैध अपेक्षा का गंभीर प्रश्न पैदा करता है। कर्मचारी ने यदि ऐसी शर्त को स्वीकार करते हुए ऑफलाइन स्टेशन पर कार्यभार संभाला, तो यह स्वाभाविक अपेक्षा बनी कि अगली ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया में उसे अनिवार्य भाग लेने का अवसर मिलेगा। बाद में उसी कर्मचारी को उस प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाए तो यह केवल तबादले का विषय नहीं रह जाता, बल्कि नीतिगत निरंतरता और प्रशासनिक विश्वसनीयता का प्रश्न बन जाता है। सरकार द्वारा पहले निर्धारित शर्त और बाद में अपनाई गई व्याख्या के बीच स्पष्टता आवश्यक है। विशेषकर वे कर्मचारी जो पहले ऑनलाइन तबादला अभियानों में भाग लेते रहे हैं, उनकी स्थिति पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। उन्होंने सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया, विकल्प दिए और ऑनलाइन व्यवस्था में भाग लिया। यदि 2022 से 2026 के बीच नियुक्त कर्मचारियों को वर्तमान अभियान में अनिवार्य रूप से शामिल नहीं किया जाता, तो पहले से ऑनलाइन प्रक्रिया में भाग लेते रहे कर्मचारियों की पसंद और अवसर भी निश्चित तौर पर प्रभावित होंगे। ऐसी स्थिति में यह सवाल स्वाभाविक है कि पहले की भागीदारी का वर्तमान प्रक्रिया में क्या महत्व रहेगा। किसी कर्मचारी को पहले ऑनलाइन व्यवस्था का हिस्सा बनाना और बाद में उसी व्यवस्था की अगली प्रक्रिया में उसके विकल्प सीमित कर देना नीतिगत निरंतरता पर प्रश्न खड़ा करता है। यहां यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि तबादले का अधिकार और तबादला प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर अलग-अलग बातें हैं।

अब 'दिमागी नक्सली', प्रधानमंत्री ने छेड़ी नई बहस..!

प्रधानमंत्री ने अपनी टिप्पणी में दिमागी नक्सली की कोई स्पष्ट या औपचारिक परिभाषा तो दी नहीं और न ही कोई कानूनी परिभाषा बताई। भले ही उनकी टिप्पणी इशारों में रही, लेकिन राजनीतिक और वैचारिक संदर्भ में इसके मायने बहुत गहरे हैं। जंतर-मंतर पर हाल ही में जिस तरह कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले छात्र आंदोलन हुआ जो देखते-देखते देश का एक बड़ा और अप्रत्याशित आन्दोलन बन खड़ा हुआ। अब उसके फैलते जाने का अंदेशा भी दिखाई दे रहा है। कहीं उसी पर तो यह टिप्पणी नहीं की? या फिर हाल ही में संसद में लगातार गतिरोध बने रहने और नेता विपक्ष राहुल गांधी के तमाम मंचों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती देने की खीझ पर तो निशाना नहीं लगया?

ऋतुपर्ण दवे

लालकिले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 80वें स्वाधीनता दिवस पर उद्बोधन के दौरान विरोधियों पर कसा गया तंज अब नई और राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है। प्रधानमंत्री की दिमागी नक्सलवाद कह कर की गई टिप्पणी ने नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री ने किसे या किन्हें दिमागी नक्सली कहा, क्या विपक्ष और आंदोलनकारी छात्रों को या सरकार पर उंगली उठाने वाले हरेक को या फिर संसद न चलने देने वाले विपक्ष को? निश्चित रूप से इस टिप्पणी पर अभी आगे काफी कुछ सियासत होनी तय है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हथियार उठाने वाले नक्सलियों से तो निपट लिया गया, लेकिन अब देश को 'दिमागी नक्सलियों' से सतर्क रहने और उन्हें अलग-थलग करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि नक्सलवाद और माओवादी हिंसा ने दशकों तक देश के बड़े हिस्से को प्रभावित किया जिसमें हजारों लोगों की जान गई। उनका इशारा था कि अब इस चुनौती के एक दूसरे स्वरूप यानी दिमागी नक्सलवाद से निपटना जरूरी हो गया है।

प्रधानमंत्री ने अपनी टिप्पणी में दिमागी नक्सली की कोई स्पष्ट या औपचारिक परिभाषा तो दी नहीं और न ही कोई कानूनी परिभाषा बताई। भले ही उनकी टिप्पणी इशारों में रही, लेकिन राजनीतिक और वैचारिक संदर्भ में इसके मायने बहुत गहरे हैं। जंतर-मंतर पर हाल ही में जिस तरह कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले छात्र आंदोलन हुआ जो देखते-देखते देश का एक बड़ा और अप्रत्याशित आन्दोलन बन खड़ा हुआ। अब उसके फैलते जाने का अंदेशा भी दिखाई दे रहा है। कहीं उसी पर तो यह टिप्पणी नहीं की? या फिर हाल ही में संसद में लगातार गतिरोध बने रहने और नेता विपक्ष राहुल गांधी के तमाम मंचों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती देने की खीझ पर तो निशाना नहीं लगया?

सच यह है कि हाल के दिनों में जेन-जी के जंतर-मंतर पर आन्दोलन के बाद 12 वर्षों में पहली बार मोदी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा। उससे भी गंभीर और बड़ी बात यह कि इस मुद्दे को विपक्ष खासकर राहुल गाँधी ने लपक लिया और संसद से सड़क तक प्रभावशाली तरीके से उठाया। निश्चित रूप से जेन-जी आन्दोलन के चलते महज युवा ही नहीं बल्कि उनके अभिभावक भी नाराज दिखे। इससे पहली बार लगा कि मोदी सरकार परेशान है। देखते ही देखते छात्रों की पिटाई, बिना वर्दी के पुलिस वालों की मौजूदगी, पैलेट गन और कील लगी लाठियों के उपयोग को राहुल ने राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। कहीं दिमागी नक्सली कहकर उनका इशारा इसी पर तो नहीं था? क्या प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल करके देश को सुरक्षा, वैचारिक स्थिरता और सामाजिक एकता से जुड़ाव रखने का साफ और कड़ा संदेश तो देने की कोशिश तो नहीं की? अपने उद्बोधन के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं को हिंसा और अराजकता से दूर रहना होगा और विकास तथा रचनात्मक कार्यों में सहयोग देना होगा। जाहिर है प्रधानमंत्री दिमागी नक्सलवाद के जरिए विरोधियों को लताड़ तो लगा रहे थे। साथ ही रूठे या उनसे नाराज जेन-जी को भी संदेश दे रहे थे कि वो रचनात्मक कार्यों में सहयोग करें। जंगली नक्सली खत्म हो गए हैं लेकिन जो दिमागी नक्सली सिर उठा रहे हैं, उन्हें पहचानने की बात किसके लिए कह गए? उन्होंने आगे जो कहा वह और भी खास है जिसमें जंगल नक्सलियों की जगह अब शहरों, शिक्षण संस्थानों और बौद्धिक मंचों पर सक्रिय दिमागी नक्सल के लेने की बात कह, सरकार का विरोध करने वालों को तिलमिला दिया। उन्होंने इनसे सावधान रहने का आगाह भी किया। हथियारबंद नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में हैं जिन्हें पहचानना होगा। उन्होंने साफ किया कि यह वर्ग सीधे हथियार नहीं उठाता, बल्कि अपनी विचारधारा से देश में भ्रम और अराजकता फैलाने की फिराक में रहता है। पहले भी अर्बन नक्सली कहे जाने पर हंगामा हुआ था जिस पर संसद में बताया गया कि संसद में अर्बन नक्सल शब्द की कोई औपचारिक कानूनी परिभाषा नहीं है। सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि कानून के तहत इस शब्दावली को परिभाषित नहीं किया गया।

हाँ, राजनीतिक बयानों और बहसों में इसका उपयोग अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा और वैचारिक विरोध के संदर्भ में किया जाता है। आगे क्या दिमागी नक्सल पर भी यही होगा। काँग्रेस ने दिमागी नक्सलवाद पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी को उनकी घबराहट बताया तो प्रधानमंत्री मोदी के दिमागी नक्सल बयान पर कॉकरोच जनता पार्टी की प्रतिक्रिया ने इस मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अब सवाल यह है कि सरकार और विपक्ष इस बहस को किस दिशा में ले जाते हैं। राजनीतिक बहस तेज हो गई है। जहाँ सीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उल्टा सरकार से सवाल पूछा कि शिक्षित युवाओं को नक्सली कहना कितना उचित है?

उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा मानसून सत्र

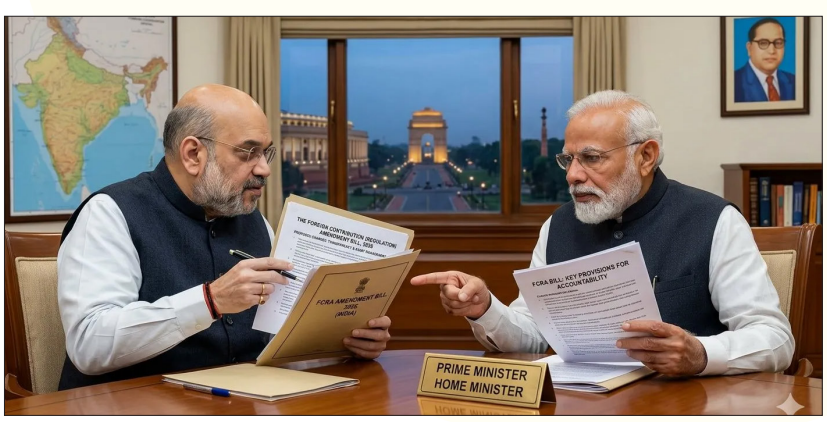

ललित गर्ग

संसदीय मर्यादाओं का क्षरण कब तक? आखिर कब हम संसद के एक-एक मिनट का उपयोग करने की पात्रता विकसित करेंगे? आजादी की 80वीं वर्षगांठ की आयोजना से पूर्व भारत में संसद का मानसून सत्र जिस निराशाजनक स्थिति, नाउम्मीदी और उपेक्षापूर्ण स्थितियां के साथ संपन्न हुआ, वह केवल किसी एक दल, सरकार या विपक्ष की विफलता नहीं है, बल्कि हमारी संसदीय संस्कृति के सामने खड़ा एक गंभीर प्रश्नचिह्न है। 25 दिनों तक चले इस सत्र में तीखी राजनीतिक बहस के बजाय हंगामा, नारेबाजी, गतिरोध और कार्यवाही बाधित करने की प्रवृत्ति अधिक प्रभावी रही। प्रश्न यह नहीं है कि सत्ता पक्ष सही था या विपक्ष, प्रश्न यह है कि क्या हमारी संसद अपने मूल दायित्व-जनता के प्रश्नों पर गंभीर विमर्श, सरकार की जवाबदेही और राष्ट्रहित में कानून निर्माण को पूरा कर पा रही है? इस सत्र के आंकड़े स्वयं बहुत कुछ कह रहे हैं। लोकसभा की उत्पादकता बमुश्किल 19 प्रतिशत रही, जबकि राज्यसभा में लगभग 39 प्रतिशत काम हो पाया। लोकसभा में एक भी दिन प्रश्नकाल पूरा नहीं हो सका। यह स्थिति इसलिए अधिक चिंताजनक है क्योंकि प्रश्नकाल संसद की आत्मा माना जाता है। देश की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को सरकार से प्रश्न पूछने और सरकार को उनका उत्तर देने का अवसर ही यदि सदन में उपलब्ध न हो, तो लोकतंत्र की जवाबदेही किस रास्ते से सुनिश्चित होगी? 28 जुलाई को लोकसभा में अपेक्षाकृत ठीक काम हुआ, जबकि राज्यसभा में भी केवल कुछ दिन ही सार्थक कार्यवाही हो सकी। शेष समय का बड़ा हिस्सा राजनीतिक टकराव की भेंट चढ़ गया। संसद केवल ईंट-पत्थर से बनी इमारत नहीं है। वह भारत की सामूहिक चेतना का सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच है। वहां देश के करोड़ों नागरिकों की आकांक्षाएं, समस्याएं और सपने पहुंचते हैं। किसान, मजदूर, विद्यार्थी, महिला, व्यापारी, युवा, गरीब और वंचित वर्ग-सभी की आवाज संसद के माध्यम से राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनती है। इसलिए संसद का एक मिनट भी केवल सांसद का समय नहीं होता, वह देश की जनता के धन, विश्वास और लोकतांत्रिक अधिकार का समय होता है। संसद का प्रत्येक व्यर्थ गया मिनट वास्तव में जनता के विश्वास से घटा हुआ एक मिनट है। दुर्भाग्य यह है कि संसद में हंगामा अब अपवाद नहीं, बल्कि संसदीय राजनीति का लगभग नियमित हथियार बनता जा रहा है। मुद्दे उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है, सरकार को घेरना विपक्ष का दायित्व है और असहमति लोकतंत्र की शक्ति है, लेकिन असहमति को संवाद में बदलने के बजाय कार्यवाही रोक देना लोकतंत्र को मजबूत नहीं करता। विरोध की भी एक मर्यादा होती है। यदि विपक्ष अपनी बात रखने के लिए सदन को चलने ही न दे और सत्ता पक्ष विपक्ष की आवाज सुनने की बजाय राजनीतिक बहुमत को ही पर्याप्त समझे, तो दोनों मिलकर संसदीय लोकतंत्र की आत्मा को कमजोर करते हैं। इस सत्र में कुछ घटनाएं इस गिरावट को और स्पष्ट करती हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने सत्र के समापन पर पारंपरिक समापन भाषण नहीं दिया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के साथ होने वाली चाय पार्टी का बहिष्कार किया जाना भी केवल एक कार्यक्रम का बहिष्कार नहीं माना जा सकता।

केंद्र ने रिफाइनरियों और उत्पादकों के लिए एलपीजी उत्पादन लक्ष्य तय किए, आपूर्ति संबंधी जोखिम को कम करने में मिलेगी मदद

» **नई दिल्ली, यूटर्न/ 16 अगस्त ।**

भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने और आयातित रसोई गैस की आपूर्ति में होने वाले व्यवधानों के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने पहली बार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों के साथ-साथ तेल एवं गैस उत्पादकों के लिए रिफाइनरी-वार और कंपनी-वार एलपीजी उत्पादन लक्ष्य तय किए हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक आदेश के जरिए ऐसा ढांचा तैयार किया है, जिसके तहत आपूर्ति में कमी आने पर 21 रिफाइनरियों और अपस्ट्रीम कंपनियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाना होगा।

नए ढांचे के तहत कुल संभावित उत्पादन क्षमता 63,810 टन प्रतिदिन तय की गई है। यह भारत की दैनिक एलपीजी खपत का लगभग 70 प्रतिशत है और देश के सामान्य घरेलू उत्पादन से काफी अधिक है।

यह कदम हालिया पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद उठाया गया है, जिसने आयातित एलपीजी आपूर्ति पर भारत की निर्भरता और उससे जुड़े जोखिमों को उजागर किया।

भारत में हर साल लगभग 3.32 करोड़ टन (करीब 91,000 टन प्रतिदिन) एलपीजी की खपत होती है। इसमें से केवल 1.31 करोड़ टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता है, जबकि जरूरत का 64 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आयात से पूरा किया जाता है। इनमें से अधिकांश एलपीजी की आपूर्ति होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते होती है।

इस साल की शुरूआत में ईरान से जुड़े संकट के दौरान इस रणनीतिक समुद्री मार्ग से शिपमेंट में व्यवधान के कारण सरकार को आपातकालीन कदम उठाने पड़े थे। इनमें रिफाइनरियों को पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक की धाराओं को एलपीजी उत्पादन की ओर मोड़कर उत्पादन अधिकतम करने का निर्देश देना भी शामिल था।

औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को एलपीजी की आपूर्ति भी सीमित की गई थी, जबकि जहां सुविधा उपलब्ध थी, वहां घरेलू उपभोक्ताओं को पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। संकट के चरम पर घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ाकर लगभग 55,000 टन प्रतिदिन कर दिया गया था।

बीमा कंपनियों को चेतावनी, सिर्फ आरोप से क्लेम खारिज नहीं, देना होगा सबूत

नई दिल्ली, यूटर्न/ 16 अगस्त । तेलंगाना राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (टीएससीडीआरसी) ने बीमा कंपनियों के लिए एक अहम फैसला सुनाया है। अब केवल जानबूझकर जानकारी छिपाने का आरोप लगाने से डेथ क्लेम खारिज नहीं होगा, बल्कि कंपनी को यह साबित भी करना होगा। आयोग ने टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस को एक परिवार को 1 करोड़ रुपये का डेथ क्लेम ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सेवानिवृत्त अधिकारी रामदास विसलावथ ने अक्टूबर 2019 में टाटा एआईए से 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी ली थी। मई 2021 में कोविड-19 से उनकी मृत्यु के बाद कंपनी ने क्लेम यह आरोप लगाकर खारिज किया कि उन्होंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के एक पुराने, टले हुए बीमा आवेदन की जानकारी छिपाई थी। हालांकि, आयोग ने कंपनी के तर्कों को खारिज कर दिया। उसने पाया कि टाटा एआईए यह साबित नहीं कर पाई कि पॉलिसीधारक को पुराने प्रस्ताव स्थगित होने या खराब मेडिकल रिपोर्ट की जानकारी थी। कंपनी ने खुद पॉलिसी जारी करने से पहले उनका मेडिकल टेस्ट किया था और फिट पाया था।

ई20 माइलेज के लिए अकेला जिम्मेदार नहीं, मिलावट के दावे भी खारिजः सरकार

नई दिल्ली, यूटर्न/ 16 अगस्त । ई20 पेट्रोल से जुड़े माइलेज में कमी और मिलावट के आरोपों पर केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि वाहनों के माइलेज में गिरावट के लिए सिर्फ ई20 को जिम्मेदार ठहराना गलत है। मंत्रालय ने ईंधन में मिलावट के दावों को भी बेबुनियाद बताया। मंत्रालय के अनुसार वास्तविक परिस्थितियों में माइलेज ड्राइविंग की आदतें, ट्रैफिक, गाड़ी का रखरखाव, टायरों में हवा का दबाव और एयर-कंडीशनर के उपयोग जैसे कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है। सरकार ने माना है कि ई10 के हिसाब से बनी पुरानी गाड़ियों में ई20 से 3 से 5 प्रतिशत तक मामूली कमी आ सकती है। ई20 पेट्रोल को लॉन्च से पहले गहन परीक्षण किया गया था, जिसमें इंजन की मजबूती और कंपैटिबिलिटी जांची गई थी। ई20 पेट्रोल में कथित मिलावट या दूषित ईंधन की शिकायतों को भी खारिज किया गया है।

बढ़ता यूरिया बिल, भारत की सब्सिडी नीति पर पुनर्विचार जरूरी

नई दिल्ली, यूटर्न/ 16 अगस्त । भारत सरकार द्वारा यूरिया पर दी जा रही भारी सब्सिडी अब मुश्किल में है। ईरान युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईंधन और उर्वरक महंगे हो गए हैं, जिससे भारत का आयात बिल बहुत बढ़ गया है। इससे रुपये पर दबाव बढ़ा है और सरकार अपने दशकों पुराने कृषि सब्सिडी मॉडल पर दोबारा विचार करने को मजबूर हो गई है। ईरान युद्ध और वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के कारण अंतरराष्ट्रीय उर्वरक कीमतें दोगुनी हो गई हैं। इसका सीधा असर भारत के यूरिया आयात बिल पर पड़ा है, जो इस वित्तीय वर्ष में अनुमानित 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है। यह भारी सब्सिडी बोझ और विदेशी मुद्रा के बाहर जाने से भारतीय रुपये पर दबाव बढ़ा है। किसान 45 किलो यूरिया के लिए मात्र 266.5 रुपये देते हैं, जबकि सरकार इसे खरीदने के लिए दस गुना ज्यादा कीमत चुका रही है। इस गंभीर स्थिति ने सरकार को अपने दशकों पुराने कृषि सब्सिडी मॉडल पर पुनर्विचार करने को विवश किया है।

मार्केट आउटलुकः कच्चे तेल की कीमतें

अमेरिका-ईरान तनाव और आर्थिक आंकड़ों से तय होगी शेयर बाजार की चाल

» **मुंबई, यूटर्न/ 16 अगस्त ।**

भारतीय शेयर बाजार के लिए अगला हफ्ता काफी अहम होने वाला है। अमेरिका-ईरान के बीच तनाव, कच्चे तेल की कीमतें, विदेशी निवेशकों की चाल और आर्थिक आंकड़ों से बाजार का रुझान तय होगा।

अमेरिका-ईरान तनाव पर अपडेट इस हफ्ते बाजार के लिए काफी अहम होंगे। दोनों देशों के बीच हॉर्मुज खोलने को लेकर बातचीत चल रही है और इसके नतीजों का इंतजार निवेशक बेसब्री से कर रहे हैं।

हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद रहने से कच्चे तेल की कीमतें उच्च स्तर पर बनी हुई हैं और ब्रेंट क्रूड 88 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड 81 डॉलर प्रति बैरल के करीब बना हुआ है।

हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया के करीब 20 प्रतिशत कच्चे तेल का निर्यात होता है।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के इनफ्लो पर निवेशकों की निगाहें बनी हुई हैं।

इस महीने की शुरूआत से एफआईआई भारतीय शेयर बाजार में शुद्ध विक्रेता बने हुए हैं। इस दौरान उन्होंने 4,115.93 करोड़ रुपए का इक्विटी में निवेश किया है। इसके अलावा, घरेलू आर्थिक डेटा भी बाजार के लिए अहम होंगे। इस दौरान बेरोजगारी डेटा, आईआईपी, पीएमआई और विदेशी मुद्रा भंडार जैसे अहम डेटा जारी किए जाएंगे।

बीते हफ्ते भारतीय शेयर बाजार का प्रदर्शन कमजोर रहा। इस दौरान सेंसेक्स 489.92 अंक या 0.62 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 78,009.25 और निफ्टी 204.65 अंक या 0.83 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,366 पर था। इस दौरन मिडकैप और स्मॉलकैप का प्रदर्शन भी मिलाजुला रहा। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स में 318.60 अंक या 0.50 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 129.25 अंक या 0.65 प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुआ। इस दौरान सूचकांकों में निफ्टी मेटल, निफ्टी कमोडिटीज, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी हेल्थकेयर, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी इन्फ्रा लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी मीडिया, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और निफ्टी रियल्टी लाल निशान में बंद हुए।

संक्षिप्त खबरें

रिकॉर्ड ऊंचाई पर चीनी, सरकार ने बड़े खरीदारों पर कसा शिकंजा

नई दिल्ली, यूटर्न/ 16 अगस्त । चीनी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। खाद्य मंत्रालय ने अब बड़े औद्योगिक खरीदारों से चीनी खपत का डेटा तलब किया है और मिलों के स्टॉक की फिजिकल जांच कर रहा है, ताकि बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाई जा सके। सॉफ्ट-ड्रिंक, आइसक्रीम, मिठाई निमार्ता और फूड प्रोसेसर जैसे बड़े खरीदार देश की कुल चीनी खपत का लगभग 65 फीसदी इस्तेमाल करते हैं। मंत्रालय ने चीनी मिलों से वित्त वर्ष 2025-26 में सीधे या एजेंट के जरिए 500 टन या उससे अधिक चीनी खरीदने वाले ग्राहकों की विस्तृत जानकारी मांगी है। यह कदम मिलों में की गई फिजिकल जांच के नतीजों पर आधारित है, जहां कुछ मामलों में बड़े खरीदारों को बेची गई चीनी का स्टॉक मिलों के गोदामों में ही मिला, लेकिन उसे मिलों ने अपने आधिकारिक ढ-2 फॉर्म में घोषित नहीं किया था।

एलपीजी ई-केवाईसी करने का आखिरी दिन, वरना छूट जाएगी सब्सिडी!

दिल्ली, यूटर्न/ 16 अगस्त । घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर सरकारी सब्सिडी का लाभ जारी रखने के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी पूरा करने के लिए आज आपके पास अंतिम मौका है। 16 अगस्त रात 12 बजे तक यह प्रक्रिया पूरी न करने वाले उपभोक्ताओं को सिलेंडर के लिए अधिक भुगतान करना पड़ सकता है और सब्सिडी से वंचित होना पड़ सकता है। सभी प्रमुख तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं को सूचित किया है कि सब्सिडी वाले दरों पर गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। ऐसा न करने पर उज्ज्वला योजना के कनेक्शनधारियों की सब्सिडी रुक सकती है और बुकिंग में भी बाधा आ सकती है।

हुंडई ने रखा 2030 तक 20 लाख कनेक्टेड कारें बेचने का लक्ष्य

नई दिल्ली, यूटर्न/ 16 अगस्त । वर्ष 2030 तक भारतीय बाजार में हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (एचएमआईएल) ने 20 लाख कनेक्टेड कारें बेचने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में कंपनी के पास 8 लाख से अधिक कनेक्टेड कारें सड़कों पर मौजूद हैं। वह 2027 तक 10 लाख का आंकड़ा पार करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। एचएमआईएल को यह सफलता अपने एआई-पावर्ड कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हुंडई ब्लूलिंक के कारण मिलने की उम्मीद है, जो अत्याधुनिक सुविधाएँ प्रदान करता है। हुंडई ब्लूलिंक सुरक्षा और सुविधा से जुड़े 70 से अधिक फीचर प्रदान करता है, जिनमें रिमोट व्हीकल मॉनिटरिंग, व्हीकल हेल्थ डायग्नोस्टिक्स, लोकेशन ट्रैकिंग, रिमोट कमांड, हुंडई पे के माध्यम से इन-कार पेमेंट और होम-टू-कार कनेक्टिविटी शामिल हैं। यह शक्तिशाली प्लेटफॉर्म पाँच भाषाओं में 450 से अधिक एआई-पावर्ड वॉइस कमांड को भी सपोर्ट करता है, जिससे उपयोगकताओं को सहज अनुभव मिलता है। कंपनी ने यह भी घोषणा की है कि उसकी आने वाली मास-मार्केट इलेक्ट्रिक एसयूवी के सभी वैरिएंट में मानक के तौर पर नेक्स्ट-जेनरेशन कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलेगी, जो कनेक्टेड मोबिलिटी के प्रति उसकी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। एचएमआईएल के एमडी और सीईओ तरुण गर्ग ने बताया कि यह कदम कनेक्टेड और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के तालमेल को मजबूत करेगा, जिससे ग्राहकों को भविष्य के लिए तैयार स्वामित्व अनुभव मिलेगा। ब्लूलिंक को 2019 में हुंडई वेन्यू में लॉन्च किया गया था और तब से इसमें कई महत्वपूर्ण अपडेट किए गए हैं।

बीएमडब्ल्यू एक्स1 एलडब्ल्यूबी 21 अगस्त को होगी लॉन्च

» **नई दिल्ली, यूटर्न/ 16 अगस्त ।**

भारत में बीएमडब्ल्यू ने अपनी नई एक्स1 एलडब्ल्यूबी मॉडल की बुकिंग शुरू कर दी है, जिसे 21 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। एक्स1 एलडब्ल्यूबी को विशेष रूप से पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए अतिरिक्त जगह और बेहतर आराम प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है। सामान्य बीएमडब्ल्यू एक्स1 की कीमत फिलहाल 50.9 लाख रुपये से 52.9 लाख रुपये के बीच है, और एक्स1 एलडब्ल्यूबी की कीमत इससे कुछ अधिक रहने की संभावना है, जो अतिरिक्त सुविधाओं और बड़े आकार को दर्शाएगी। लॉन्च के बाद, यह भारत में बीएमडब्ल्यू की सबसे सुलभ लंबी-दूरी वाली लग्जरी एसयूवी बन सकती है, जिससे अधिक ग्राहक लग्जरी अनुभव का लाभ उठा सकेंगे। यह नई एसयूवी सामान्य एक्स1 की तुलना में काफी बड़ी है, जिसकी लंबाई 4,616 मिलीमीटर (116 मिलीमीटर अधिक) और व्हीलबेस 2,802 मिलीमीटर (110 मिलीमीटर अधिक) है। इन बढ़े हुए आयामों से पीछे की सीट पर पैर फैलाने के लिए पर्याप्त जगह मिलेगी। पीछे की सीट की ऊंचाई में भी 27 मिलीमीटर की वृद्धि की गई है, और सामान रखने की क्षमता भी सामान्य एक्स1 के 476 लीटर के मुकाबले बढ़ाकर 540 लीटर की गई है।

केबिन में 10.7 इंच की मनोरंजन और सूचना स्क्रीन तथा 10.25 इंच का डिजिटल चालक प्रदर्शन, वायरलेस मोबाइल चार्जिंग, आगे की सीटों के लिए विद्युत समायोजन, स्वचालित तापमान नियंत्रण और स्वचालित पीछे का दरवाजा जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। बेहतर ध्वनि अनुभव के लिए हरमन कार्डन की ध्वनि प्रणाली और स्वचालित पार्किंग सुविधा भी मिलने की उम्मीद है, जो लग्जरी अनुभव को और बढ़ाएगी। भारत के लिए इंजन विकल्पों की पुष्टि लॉन्च के समय होगी, हालांकि चीन में यह 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आती है। यह मॉडल बीएमडब्ल्यू के चेन्नई स्थित संयंत्र में स्थानीय स्तर पर असेंबल किया जाएगा, जिससे इसकी कीमत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

संक्षिप्त खबरें

वंदे मातरम विवाद पर मनोज तिवारी का कांग्रेस पर हमला

नई दिल्ली, यूटर्न/ 16 अगस्त । बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने रविवार को कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टी के मन में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के प्रति गहरी बेचैनी और अनादर की भावना है।तिवारी की यह टिप्पणी नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में 'वंदे मातरम' के पूरे गायन को लेकर हुए राजनीतिक विवाद के बाद आई है। सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान उनकी साफ दिख रही बेचैनी ने उनकी असल सोच को उजागर कर दिया। बीजेपी नेता ने कहा, 'कल कांग्रेस ने देश और दुनिया के सामने अपना असली चेहरा दिखा दिया।

जेपी नड्डा अस्पताल में भर्ती डॉक्टरों ने डिस्चार्ज को लेकर नहीं लिया निर्णय

दिल्ली, यूटर्न/ 16 अगस्त । भारतीय जनता पार्टी (इखढ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की स्वास्थ्य स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। उन्हें उपचार और चिकित्सकीय निगरानी के लिए दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (अक्क्टर) में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, जेपी नड्डा की हालत में कोई गंभीर गिरावट नहीं है और उनका इलाज निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जारी है। हालांकि, उन्हें अस्पताल से छुट्टी कब दी जाएगी, इस पर चिकित्सकों ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। डॉक्टरों का कहना है कि मरीज की स्थिति, जांच रिपोर्ट और स्वास्थ्य में सुधार को ध्यान में रखते हुए ही डिस्चार्ज का निर्णय लिया जाएगा।

रेलवे स्टेशनों पर लापरवाही का खुलासा यात्रियों की सेहत पर मंडराया खतरा

» **नई दिल्ली, यूटर्न/ 16 अगस्त**

देश के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधाओं और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। निरीक्षण के दौरान कई स्टेशनों पर पेयजल में बैक्टीरिया पाए जाने और वाशरूम में गंदगी की शिकायतें सामने आई हैं। इससे यात्रियों के स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। जांच में सामने आया कि कुछ रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध पेयजल निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरा। पानी के नमूनों में बैक्टीरिया की मौजूदगी मिलने से यात्रियों के लिए स्वास्थ्य जोखिम बढ़ने की आशंका जताई गई है। अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता व्यवस्था को लेकर किए गए निरीक्षण में कई जगह वाशरूम की स्थिति भी खराब पाई गई। शौचालयों में सफाई की कमी, गंदगी और नियमित रखरखाव में लापरवाही जैसी समस्याएं सामने आईं।

रेलवे यात्रियों की बड़ी संख्या रोजाना स्टेशनों पर पहुंचती है। ऐसे में साफ पानी और स्वच्छ शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं बेहद जरूरी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि दूषित पानी से पेट संबंधी बीमारियां, संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अधिकारियों ने कहा है कि जहां भी कमियां मिली हैं, वहां संबंधित विभागों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए हैं। पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नियमित जांच और सफाई व्यवस्था की निगरानी बढ़ाने की बात कही गई है। रेलवे प्रशासन लंबे समय से स्टेशनों को बेहतर और आधुनिक बनाने की दिशा में काम कर रहा है।

कल्याणपुरी में सफाई कर्मचारी की चाकू मारकर हत्या

भाजपा विधायक ने पीड़ित परिवार को दिया न्याय का भरोसा

» **नई दिल्ली, यूटर्न/ 16 अगस्त** ।

दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में ड्यूटी के दौरान दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के एक सफाई कर्मचारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी में आरोपी को सफाई कर्मचारी पर चाकू से हमला करते हुए देखा गया। फिलहाल, दिल्ली पुलिस की टीम हमलावर का पता लगाने के लिए फुटेज और अन्य सबूतों की जांच कर रही है।

मृतक की पहचान 24 वर्षीय अनिल कुमार के तौर पर हुई है, जो एमसीडी में सफाई कर्मचारी थे। शुरूआती जानकारी के मुताबिक, रविवार सुबह करीब 7 बजे अनिल कल्याणपुरी में अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तभी उन पर चाकू से हमला किया गया।

घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गया। सीसीटीवी में देखा गया कि आरोपी ने चाकू ले रखा था और उसने सफाई कर्मचारी अनिल के चाकू मार दिया, जहां उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाईं। इस घटना के बाद भाजपा विधायक रविकांत मौके पर पहुंचे।

उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि यह बेहद दुखद घटना है। यह सच्चाई है कि जब पूरी दिल्ली सो रही होती है, तो उसे जगाने का काम यही कर्मचारी करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं।

घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गया। सीसीटीवी में देखा गया कि आरोपी ने चाकू ले रखा था और उसने सफाई कर्मचारी अनिल के चाकू मार दिया, जहां उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

भाजपा विधायक ने बताया कि जिस व्यक्ति ने वारदात को अंजाम दिया है, उसकी पहचान की जा चुकी है। उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विधायक रविकांत ने आगे कहा, 'मैंने सीसीटीवी देखा है। अनिल अपना काम कर रहा था। आरोपी ने अचानक आकर हमला किया।' वहीं, आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, 'कल्याणपुरी में एक सफाई कर्मचारी की खुले आम हत्या कर दी गई। क्या कल्याणपुरी अपराध की राजधानी बन गई है? पूरी दिल्ली में हत्याएं हो रही हैं।'

उन्होंने कहा, 'एक सफाई कर्मचारी जो अपना काम करता है, उसके परिवार की हालत के बारे में सोचिए। जब वह कचरा उठाता है, तो ऐसा इसलिए नहीं करता कि उसे यह काम पसंद है। आर्थिक हालात की वजह से उसे कोई और नौकरी नहीं मिलती, इसलिए उसे कचरा उठाना पड़ता है। उसकी हत्या कर दी गई है।'

कुलदीप कुमार ने कहा कि हमने पुलिस से मांग की है कि तुरंत प्रभाव से आरोपी व्यक्ति का एनकाउंटर कराया जाए, ताकि मिसाल पेश हो और कोई ऐसी वारदात को अंजाम न दे सके। उन्होंने यह भी मांग की कि पीड़ित परिवार को मुआवजा और किसी सदस्य को नौकरी दी जानी चाहिए।

दिल्ली पुलिस की कार्रवाई : जुआ, शराब और चोरी के 3 मामलों में 9 आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, यूटर्न/ 16 अगस्त । दिल्ली पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में जुआ, अवैध शराब और चोरी के तीन मामलों में कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कैश, ताश के पत्ते और अवैध शराब भी बरामद की है। खजूरी खास थाना पुलिस को शनिवार रात करीब 8 बजे सूचना मिली कि ई-ब्लॉक, श्री राम कॉलोनी, गली नंबर 2 के सामने कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलते ही हेड कांस्टेबल रोहित, हेड कांस्टेबल जुबैर और कांस्टेबल प्रमोद ने एसएचओ को जानकारी देकर मौके पर छापा मारा। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे, लेकिन टीम ने छह लोगों को पकड़ लिया। मौके से एक ताश की गड्डी और 10,440 रुपए बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में हनीफ (60), आशिफ (29), मोहम्मद सलीम (30), राजू, (60), हनीफ (38), और मोहम्मद सलीम (40) शामिल हैं। इस मामले में थाना खजूरी खास में एफआईआर दर्ज की गई। जांच के दौरान किसी की भी कोई पुरानी संलिप्तता नहीं मिली। आगे की जांच जारी है। इसी तरह सोनिया विहार पुलिस ने शनिवार शाम 6:30 बजे गश्त के दौरान बेदी गैस एजेंसी के पास एक खाली प्लॉट में एक महिला को संदिग्ध हालत में खड़े देखा। तलाशी लेने पर उसके बैग से 30 बीयर, 30 हाफ और 49 क्वार्टर की अलग-अलग ब्रांड की अवैध शराब की बोतलें मिलीं। सूचना पर हेड कांस्टेबल राज हसन और महिला कांस्टेबल यास्मीन मौके पर पहुंचीं और 52 वर्षीय महिला को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि आरोपी पहले भी इसी तरह के एक मामले में शामिल रह चुकी है। थाना सोनिया विहार में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस शराब सप्लाई के स्रोत का पता लगा रही है।

दिल्ली को विकसित भारत विजन से जोड़ने की तैयारी

» **नई दिल्ली, यूटर्न/ 16 अगस्त** ।

दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने शनिवार को 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी की विकास प्राथमिकताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक 'विकसित भारत' के विजन से जोड़ने का काम किया। उन्होंने केंद्र और दिल्ली सरकारों, नागरिक निकायों, पड़ोसी राज्यों और नागरिकों के बीच बेहतर तालमेल की अपील की। संधू ने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों, फ्हअ प्रतिनिधियों, युवा आइकन, छात्रों और निवासियों की मौजूदगी में लोक निवास में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। पुलिस की एक औपचारिक टुकड़ी ने राष्ट्रीय सलामी दी।

अपने संबोधन में, उपराज्यपाल ने दिन में लाल किले से दिए गए मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण का ज़िक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री का 'शक्ति की सप्तधारा' का विजन दिल्ली के लिए खास तौर पर प्रासंगिक है। भाषण में बताई गई सात धाराओं में मैन्युफैक्चरिंग, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी, और भारत की सॉफ्ट पावर शामिल हैं। संधू ने दिल्ली के निवासियों से अपील की कि वे राजधानी के विकास को शहर की सीमाओं से आगे ले जाएं और 'विकसित भारत @ 2047' के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने में मदद करें। उन्होंने कहा कि दिल्ली को 'विकसित दिल्ली' बनने की दिशा में काम करना चाहिए और उत्कृष्टता, सुरक्षा और नागरिक गर्व के राष्ट्रीय मॉडल के रूप में उभरना चाहिए।

विकास के एजेंडे को दिल्ली के साथ अपने लंबे जुड़ाव से जोड़ते हुए, संधू ने कहा कि वह पिछले 50 वर्षों से इस शहर को जानते हैं और यहां काम कर चुके हैं। उन्होंने दिल्ली को अपनी 'कर्मभूमि' बताया और कहा कि राजधानी की सेवा केवल एक प्रशासनिक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक पवित्र ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के हर ज़िले, सड़क और मोहल्ले की अपनी कहानी है और तर्क दिया कि शहर की क्षमता को 'हर नागरिक के लिए सुविधा, सम्मान और भलाई' में बदला जाना चाहिए।

संबोधन का मुख्य संदेश तालमेल पर केंद्रित था। संधू ने कहा कि दिल्ली का सार्वजनिक प्रशासन प्रधानमंत्री के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के संकल्प पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि राजधानी के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, नगर निकायों, पड़ोसी राज्यों और नागरिकों को मिलकर काम करने की जरूरत होगी। उन्होंने जिन मुद्दों की पहचान की, उनमें यमुना की सफाई, वायु प्रदूषण से निपटना, सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना, सस्ती स्वास्थ्य सेवाएँ देना, सुरक्षा और संरक्षा (खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए) को बेहतर बनाना, ट्रैफिक का प्रबंधन करना और दिल्ली की विरासत को फिर से जीवंत करना शामिल था।

बुनियादी ढाँचे, सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रदूषण, सुरक्षा और विरासत को अलग-अलग मुद्दों के तौर पर देखने के बजाय, एल-जी ने उन्हें एक ऐसे शहर के निर्माण के बड़े काम के हिस्से के रूप में पेश किया जो राष्ट्रीय विकास के विजन को आगे बढ़ा सके।

संधू ने इस प्रक्रिया में नागरिकों, खासकर युवाओं की भूमिका के बारे में भी बात की। उन्होंने युवाओं को दिल्ली के भविष्य का मुख्य चालक बताया और कहा कि उनकी ऊर्जा, रचनात्मक विचार और नागरिक भावना ही आधुनिक दिल्ली की असली ताकत हैं। उन्होंने नागरिकों से अपने आस-पड़ोस को साफ रखने, सार्वजनिक जगहों की सुरक्षा करने और अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करने का आ'ान किया। संधू ने कहा, 'सरकार सुंदर सार्वजनिक जगहें तो बना सकती है, लेकिन उन्हें बनाए रखने का काम सिर्फ. नागरिक ही कर सकते हैं।'

उन्होंने खास तौर पर युवाओं, इन्फ्लुएंसर्स, फ्हअ, व्यापारियों और नागरिकों से सकारात्मक भावना के साथ इसमें शामिल होने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि किसी शहर की गुणवत्ता इस बात से झलकती है कि वह अपने कमजोर वर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता है, और जो शहर सचमुच उनकी परवाह करता है, वही एक सच्चे सभ्य और प्रगतिशील समाज की पहचान है। उनका संबोधन दिल्ली को दुनिया की एक प्रमुख राजधानी बनाने के संकल्प के साथ समाप्त हुआ, जिसमें विरासत और आधुनिकता का मेल हो, सेवाएँ बेहतर हों और नागरिक सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त महसूस करें। संधू की अपील थी कि दिल्ली देश के केंद्र में अपनी स्थिति का लाभ उठाकर गवर्नेंस, नागरिक ज़िम्मेदारी और जनसेवा का एक मॉडल बने, ताकि भारत 'विकसित भारत @ 2047' के लक्ष्य की ओर बढ़ सके।

दिल्ली के होटल में मेकअप आर्टिस्ट से दुष्कर्म का आरोप, इंस्टाग्राम पर हुई थी युवक से दोस्ती

नई दिल्ली, यूटर्न/ 16 अगस्त । उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में एक होटल में 22 वर्षीय मेकअप आर्टिस्ट से कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि इंस्टाग्राम के जरिए दोस्त बने एक युवक ने उसे कथित तौर पर नशीला पदार्थ मिला कोल्ड ड्रिंक पिलाया और बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद युवती की हालत गंभीर होने पर उसे राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

पुलिस के अनुसार, पीड़िता पेशे से मेकअप आर्टिस्ट है। उसकी कुछ समय पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के माध्यम से आरोपी युवक से जान-पहचान हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी। आरोप है कि इसी जान-पहचान का फायदा उठाते हुए युवक ने पीड़िता को मिलने के लिए बुलाया। दोनों मुखर्जी नगर इलाके में स्थित एक होटल पहुंचे, जहां कथित घटना हुई। पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि होटल में युवक ने उसे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दी। इसे पीने के कुछ समय बाद उसे चक्कर आने लगे और वह कथित तौर पर बेहोश हो गई। आरोप है कि इसी अवस्था का फायदा उठाकर युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

जैस्मिन भसीन की गई याददाश्त

खतरों के खिलाड़ी 15 इन दिनों अपने खतरनाक स्टंट्स और उनसे जुड़े विवादों को लेकर सुर्खियां बटोर रहा है। मुश्किल टास्क के लिए मशहूर इस रियलिटी शो में हाल ही में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। बिग बॉस 14 से अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री जैस्मिन भसीन इस सीजन का हिस्सा हैं और हाल ही में उन्हें एक खतरनाक पानी का स्टंट करते हुए देखा गया। इस स्टंट के दौरान जैस्मिन अचानक पानी में गिर गईं, जिसके बाद उनकी हालत देखकर सेट पर मौजूद पूरी सेफ्टी टीम घबरा गई। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस हादसे के बाद जैस्मिन को कुछ समय के लिए कुछ भी याद नहीं रहा, जिससे उनके फैंस भी चिंता में पड़ गए। हालांकि फैंस के मन में सवाल उठ रहे थे कि क्या यह सिर्फ प्रोमो का हिस्सा था या सचमुच हादसा हुआ, लेकिन रिपोर्ट्स ने पुष्टि की है कि यह कोई प्रैंक नहीं था। पानी में गिरने के बाद जैस्मिन को सच में याददाश्त से जुड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्टंट खत्म होने के बाद उन्हें यह तक याद नहीं था कि अभी-अभी उनके साथ क्या हुआ है। इस घटना से सेट पर मौजूद सभी लोग तनाव में आ गए।

मलयालम फिल्मों के सितारे निन पाउली के साथ नजर आएगी रुक्मिणी

जल्द ही अभिनेत्री रुक्मिणी वसंत मलयालम फिल्मों के सितारे निन पाउली के साथ परदे पर नजर आएगी। अभिनेत्री ने अपनी अगली फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है, जिससे उनकी बढ़ती हुई फिल्मोग्राफी में एक और रोमांचक परियोजना जुड़ गई है। हाल ही में रुक्मिणी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिल्म के क्लैपबोर्ड की एक झलक साझा करते हुए आधिकारिक तौर पर शूटिंग शुरू होने की घोषणा की। यह फिल्म फिलहाल एनपी51 के नाम से जानी जा रही है। सेट से एक झलक साझा करते हुए, रुक्मिणी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, और बस, यह सफर शुरू हो गया एनपी51। किसी ऐसी जगह का हिस्सा बनना, जिसे आपने इतने लंबे समय तक दूर से निहारा और सराहा हो, अपने आप में बेहद खास एहसास है। और अब उसी जगह का एक छोटा सा हिस्सा बन पाना मेरे लिए वाकई बहुत स्पेशल फर्स्ट है। इस प्रोजेक्ट के लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ । इस परियोजना से जुड़ी टीम भी इसकी एक्साइटमेंट को और बढ़ा रही है।

इस फिल्म को चार्ली और नयट्टु जैसी शानदार फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले फिल्ममेकर-प्रोड्यूसर मार्टिन प्रक्कट का समर्थन मिला है। वहीं, जय जय जय जय जय हे के लेखकों में शामिल रहे नाशिद इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं। रुक्मिणी वसंत और निन पाउली के साथ इन प्रतिष्ठित नामों का जुड़ना एनपी51 को मलयालम सिनेमा की सबसे दिलचस्प आगामी फिल्मों में से एक बना रहा है। सप्त सागरदाचे एलो और कांतारा जैसी फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से रुक्मिणी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कभी सिर्फ एक होनहार कन्नड़ प्रतिभा के तौर पर देखी जाने वाली रुक्मिणी अब धीरे-धीरे पूरे साउथ इंडियन सिनेमा में सबसे ज्यादा डिमांड वाली युवा अभिनेत्रियों में अपनी जगह बना चुकी हैं।

रुक्मिणी अब टॉक्सिकः ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स को लेकर भी तैयार हैं, जिसमें वह एक महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगी। इसके अलावा, उनके खाते में एनटीआरनील की बहुप्रतीक्षित बड़ी फिल्म ड्रैगन भी है। शानदार परफॉर्मेंस, अलग-अलग तरह के किरदार और बड़े पैन-इंडियन प्रोजेक्ट्स के साथ रुक्मिणी का करियर पूरी गति से आगे बढ़ रहा है।

मोड्रिक अब 2027 तक एसी मिलान के साथ रहेंगे

» रोम, यूटर्न/ 16 अगस्त ।

क्रोएशियाई फुटबॉलर लुका मोड्रिक अब साल 2027 तक इटली के क्लब एसी मिलान के साथ ही रहेंगे। मोड्रिक ने क्लब के साथ अपने अनुबंध को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है। इसी के साथ ही अब मोड्रिक जून 2027 तक मिलान की ओर से खेलेंगे। सितंबर में 41 साल के होने जा रहे इस क्रोएशियाई खिलाड़ी का यह फैसला उनके असाधारण खेल भावना और मैदान पर बने रहने की उनकी अटूट इच्छा को दर्शाता है। गौरतलब है कि पिछले साल, मोड्रिक ने स्पेनिश टीम रियल मैड्रिड के साथ अपने 13 साल के करार को तोड़कर मिलान से करार किया था। वहीं रियल के साथ अनुबंध समाप्त होने के बाद उन्होंने नए अध्याय की शुरूआत की थी।

एसी मिलान के लिए अपने पहले सत्र में उन्होंने कुल 37 मुकाबले खेले और दो अहम गोल किये। हालांकि, टीम का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, और वह सेरी ए में पांचवें स्थान पर रही जबकि कोपा इटालिया में अंतिम-16 दौर से आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बावजूद, मोड्रिक का अनुभव और मैदान पर उनकी उपस्थिति टीम के लिए काफी लाभदायकर रही। मोड्रिक ने पहले फीफा विश्व कप 2026 के बाद संन्यास की बात कही थी पर अब उन्होंने क्लब फुटबॉल के साथ ही बने रहना तय किया है।

मिलान ने अपने बयान में मोड्रिक के करार बढ़ाने की पुष्टि करते हुए उनकी जमकर तारीफ की। क्लब ने कहा कि मिडफील्ड में आने के बाद से, मोड्रिक ने अपने अपार अनुभव, अथक मेहनत और अद्वितीय खेल कौशल से टीम को लगातार मजबूती दी है। वे आने वाले सत्र में भी टीम के लिए एक अहम भूमिका निभाएंगे और नंबर-14 की अपनी जर्सी में नजर आयेंगे।

वह साल 2012 में इंग्लैंड के टोटेनहम हॉटस्पर से रियल मैड्रिड आए थे, जहाँ उन्होंने शुरूआती मुश्किलों के बावजूद अपने क्लब इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में अपने को साबित किया।

अश्विन ने की रोहित और कोहली को लेकर भविष्यवाणी

» चेन्नई, यूटर्न/ 16 अगस्त ।

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने दिग्गज बल्लेबाजों रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर भविष्यवाणी की है। अश्विन के अनुसार जहां रोहित इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से संन्यास के बाद मुम्बई इंडियंस में कोच बनेंगे। वहीं विराट अपनी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) में कोच नहीं बनेंगे। रोहित और कोहली अपने शानदार क्रिकेट के अंतिम चरण में हैं जिसके कारण प्रशंसक संन्यास के बाद जानना चाहते थे कि ये दोनो क्या करेंगे। अश्विन ने इसी को लेकर कहा कि जहाँ रोहित कोचिंग की भूमिका के लिए तैयार हो सकते हैं, वहीं कोहली संभवतः खेल से कुछ समय के लिए दूरी बना सकते हैं। अश्विन ने एक कार्यक्रम में कहा उन्हें नहीं लगता कि विराट एकदम से कोचिंग की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होंगे। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि विराट तुरंत कोच बनने के लिए तैयार होंगे। वह शायद खेल से ब्रेक लेना चाहेंगे। अश्विन ने कहा कि कोहली अपने अत्यधिक प्रतिस्पर्धी स्वभाव और खेल के प्रति गहन जुनून के बाद शायद कुछ समय के लिए शांति और आराम करना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि वे तुरंत एक नई, गहन भूमिका में उतरें, जिसके लिए उतनी ही प्रतिबद्धता और ऊर्जा की आवश्यकता होती है।

दूसरी ओर अश्विन का मानना है कि यदि रोहित शर्मा अपने खेलने के करियर को समाप्त करने का फैसला करते हैं, तो मुंबई इंडियंस को उन्हें तुरंत अपने डगआउट में शामिल कर लेना चाहिए। अश्विन ने जोर देकर कहा, अगर कल रोहित यह तय करते हैं कि मैं नहीं खेलूंगा, तो मुंबई इंडियंस को तुरंत उन्हें शामिल कर लेना चाहिए। एक ऐसा कप्तान जिसने पांच खिताब जीते हों और भारत को विश्व कप में अपनी कप्तानी से नेतृत्व दिया हो झ ऐसे लोग आसानी से नहीं मिलते। अश्विन ने रोहित के अपार अनुभव और नेतृत्व गुणों पर प्रकाश डाला, जो किसी भी टीम के लिए अमूल्य साबित हो सकते हैं।

अश्विन ने अपनी राय रखते हुए आगे कहा कि भले ही रोहित तुरंत हेड कोच जैसी अत्यधिक मेहनत वाली भूमिका नहीं निभाना चाहें, फिर भी एक-दो साल के ब्रेक के बाद वे किसी अन्य भूमिका में वापसी कर सकते हैं।

यूटर्न टाइम
THE GOOD, BAD & UGLY OF INDIA

बेल्जियम में लगी भीषण आग से हाहाकार, 2,000 हेक्टेयर जमीन जलकर राख

» ब्रसेल्स, यूटर्न/ 16 अगस्त ।

बेल्जियम में आग लगने से हाहाकार मच गया है। आग इतनी भीषण है कि 2,000 हेक्टेयर जमीन जलकर राख हो गई है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि शनिवार शाम तक बेल्जियम के पूर्वी इलाके 'हाई फेन्स' में लगी देश की अब तक की सबसे भीषण आग की वजह से लगभग 2,000 हेक्टेयर वनस्पति जलाकर राख हो गई है।

वालून पब्लिक सर्विस की ओर से पुष्टि की गई है कि जंगल की आग से जलने वाले सबसे बड़े इलाके का राष्ट्रीय रिकॉर्ड इस आग ने बनाया है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे आग लगने के बाद लगभग 30 घंटे तक आग बुझाने

का काम जारी रहा।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, आस-पास के इलाकों से करीब 600 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। एहतियात के तौर पर वाइम्स नगरपालिका के सौरब्रॉड्ट इलाके के करीब 500 लोगों और बुटजेनबैक के करीब 100 लोगों को वहां से हटाया गया। सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के आदेश सौरब्रॉड्ट की 15 सड़कों और बुटजेनबैक की सात सड़कों के लिए लागू किए गए थे।

ईयू सिविल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म के तहत अंतरराष्ट्रीय मदद जुटाई जा रही थी। आग पर काबू पाने के लिए डच सेना के दो हेलीकॉप्टर, चेक गणराज्य का एक फायरफाइटिंग हेलीकॉप्टर और स्वीडन के दो फायरफाइटिंग विमान तैनात किए गए। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि हवाओं की वजह से आग बुझाने में परेशानी हो रही थी और आग के बढ़ने का भी खतरा बढ़ गया था।

इससे पहले बेल्जियम ने आग बुझाने में अतिरिक्त मदद के लिए यूरोपीय संघ के सिविल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को सक्रिय करने का अनुरोध किया था। शनिवार को ईयू के बेड़े से एक हेलीकॉप्टर और दो फायरफाइटिंग विमान बेल्जियम के लिए रवाना हुए थे। शनिवार दोपहर तक आग बेकाबू बनी हुई थी।

ईरान साइबर हमलों का मुकाबला करने के लिए लगातार काम कर रहा : मंत्री

» तेहरान, यूटर्न/ 16 अगस्त ।

ईरान का दावा है कि वो हथियारों से ही नहीं साइबर हमलों का भी सामना कर रहा है। देश के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्री सत्तार हशमी ने रविवार को कहा कि हालिया संघर्ष के बीच ईरान पर लगातार साइबर अटैक जारी है।

ईरान की आधिकारिक न्यूज एजेंसी आईआरएनए की रिपोर्ट के मुताबिक, हशमी ने कहा, 'हम जंग जैसे हालात से जूझ रहे हैं, हम पर लगातार साइबर अटैक हो रहे हैं, लेकिन हमारे साथी साइबर अटैक का मुकाबला करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं।

हमारे युवाओं और प्रबुद्ध लोगों ने इन हमलों को भलीभांति और सुरक्षित तरीके से मैनेज किया है।' उन्होंने यह भी कहा कि समय के साथ हमले का तरीका भी बदलता रहता है। उन्होंने बताया कि पहले साइबर अटैक को रोकने में देश के अनुभव ने इन परेशानियों को बखूबी रोका और 'दुश्मनों' के मकसद को नाकाम कर दिया।

वहीं, शनिवार को, ईरान और ओमान

होर्मुज स्ट्रेट के जरिए वाणिज्यिक जल मार्ग पर सहमत हुए, लेकिन दोनों के बीच अब भी कुछ तकनीकी पक्षों को लेकर बातचीत जारी है। फिलहाल दोनों किसी समझौते पर नहीं पहुंचे हैं।

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि पिछले तीन हफ्तों में बातचीत अच्छे तरीके से आगे बढ़ी है। दोनों देश संयुक्त बयान की शब्दावली को लेकर भी मंथन कर रहे हैं। बाघेई ने आगे कहा, 'अभी भी कुछ मामलों पर चर्चा जारी है, खासकर ईरान और ओमान द्वारा जारी किए जाने वाले जॉइंट स्टेटमेंट को लेकर बातचीत चल रही है। जब भी इस पर फैसला लिया जाएगा, सबको पता चल जाएगा।'

ईरानी अधिकारियों के हवाले से कहा जा रहा है कि, दोनों तटीय देश स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के लिए एक 'शिपिंग मैप' पर सहमत हो गए हैं। आगे चलकर बाकी तकनीकी पक्ष पर बात होगी। इस मसले पर ईरान और ओमान ने अलग-अलग बातचीत की थी। अमेरिका इस का हिस्सा नहीं था।

औपचारिक रूप से युद्ध खत्म करने के दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली के प्रस्ताव पर प्योंगयांग खामोश

» सोल, यूटर्न/ 16 अगस्त ।

उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग की उस पहल पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जिसमें उन्होंने 1950-53 के कोरियाई युद्ध को औपचारिक रूप से समाप्त करने और स्थायी शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए बातचीत का प्रस्ताव दिया था। योनहाप न्यूज एजेंसी ने बताया कि ली ने शनिवार को देश के मुक्ति दिवस के मौके पर दिए अपने संबोधन में उत्तर कोरिया के साथ संवाद बहाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को लंबे समय से चले आ रहे टकराव को समाप्त करने और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की दिशा में आगे बढ़ने के प्रयास करने चाहिए। हालांकि, उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने रविवार सुबह तक ली के संबोधन को लेकर कोई खबर प्रकाशित नहीं की। सरकारी समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) और रोडोंग सिनमुन ने इसके बजाय जापानी औपनिवेशिक शासन से कोरिया की मुक्ति की 81वीं वर्षगांठ से जुड़े देशभर के कार्यक्रमों को प्रमुखता दी।

ईरान और ओमान के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य के लिए समुद्री मानचित्र पर समझौता

तेहरान, यूटर्न/ 16 अगस्त । ईरान और ओमान के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य के लिए समुद्री मानचित्र पर समझौता हो गया है, हालांकि कुछ मुद्दों पर अभी भी बातचीत चल रही है। प्रेस टीवी ने ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई के हवाले से यह जानकारी दी है। इससे पहले सऊदी ब्रॉडकास्टर अल-हदाथ ने खबर दी थी कि ईरान और ओमान के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य को परिवहन के लिए पूरी तरह खोलने पर समझौता हुआ है, जिसे ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की मंजूरी मिलनी बाकी है। चैनल के अनुसार इस समझौते की आधिकारिक घोषणा आने वाले दिनों में की जाएगी। हाल के हफ्तों में अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया के मध्यस्थों की मदद से संघर्ष को खत्म करने के लिए एक नए समझौते की शर्तों पर सहमत होने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गत नौ अगस्त को कहा था कि अमेरिका ईरान के साथ बहुत धीमी गति से बातचीत कर रहा है, जबकि ईरान की आर्थिक स्थिति कथित तौर पर और खराब हो गई है।

समुद्री बचाव दल ने ब्रिटेन जाने के लिए इंग्लिश चैनल पार कर रहे 82 प्रवासियों को बचाया

पेरिस, यूटर्न/ 16 अगस्त । उत्तरी फ्रांस में समुद्री बचाव दल ने ब्रिटेन जाने के लिए इंग्लिश चैनल पार करने की कोशिश कर रहे 82 प्रवासियों को बचा लिया है। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के समुद्री प्रीफेक्चर ने यह जानकारी दी। प्रीफेक्चर ने एक्स पर कहा, 'विभाग की अग्निशमन और बचाव सेवा ने उन 82 लोगों को बचाया जो चैनल पार करना चाहते थे।' यह अभियान बर्क-सुर-मेर शहर के उत्तर में चलाया गया। 2025 में 41,000 से ज्यादा अवैध प्रवासी नाव के जरिए इंग्लिश चैनल से होकर ब्रिटेन पहुँचे।

भारत-बंगलादेश की साझेदारी को अहम क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए आपसी सहयोग जरुरी : दिनेश त्रिवेदी

ढाका, यूटर्न/ 16 अगस्त । बंगलादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने शनिवार को कहा कि भारत-बंगलादेश की साझेदारी को अहम क्षेत्रों में आगे बढ़ाने और दोनों देशों के बीच दोस्ती को मजबूत करने के लिए आपसी सहयोग बहुत जरुरी है। श्री त्रिवेदी ने बंगलादेश की राजधानी ढाका में भारतीय उच्चायोग में भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा, 'हम मानते हैं कि साझा उम्मीदों और आपसी सद्भावना पर टिका लोगों के बीच का आपसी जुड़ाव ही इस मजबूत दोस्ती की असली जान है। आइए, हम भारत और बंगलादेश के बीच दोस्ती के खास रिश्तों को और मजबूत करें और साझा समृद्धि की दिशा में मिलकर काम करें।' दोनों देशों के रिश्तों की नींव पर बात करते हुए उच्चायुक्त ने कहा कि भारत और बंगलादेश आजादी की लड़ाई के साझा इतिहास से जुड़े हैं और उनके रिश्ते आपसी सम्मान और साझेदारी पर बने हैं। उन्होंने कहा , 'आजादी की लड़ाई के इतिहास के साथ हमारा रिश्ता गहराई से जुड़ा हुआ है। साझा इतिहास, आपसी सम्मान और साझेदारी की इस मजबूत नींव पर हमारे रिश्ते लगातार फल-फूल रहे हैं।' भविष्य के दृष्टिगत उन्होंने भारत के लगातार विकास, एकता और समृद्धि के लिए नये सिरे से प्रतिबद्धता जताने का आ'न किया। उन्होंने कहा, 'आज हम न केवल अपनी आजादी की शुरूआत का जश्न मना रहे हैं, बल्कि अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं की मजबूती और आधुनिक भारत की शानदार विकास गाथा का भी जश्न मना रहे हैं।

इंडियाना में तीन दशक की सबसे भीषण बाढ़, छह की मौत

» वाशिंगटन, यूटर्न/ 16 अगस्त ।

अमेरिकी राज्य इंडियाना में भारी बारिश के बाद आई भीषण बाढ़ ने बड़े स्तर पर तबाही मचा दी है। अधिकारियों के अनुसार, राज्य में चार साल के बच्चे समेत छह लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई इलाकों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसे पिछले तीन दशकों में राज्य की सबसे गंभीर बाढ़ की घटनाओं में से एक बताया जा रहा है।

इंडियाना स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन्स सेंटर ने कहा कि मरने वालों में तीन महिलाएं और दो पुरुष भी शामिल हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, डेलावेयर काउंटी में दो और जेनिंग्स, लेक, पोर्टर और लापोर्ट काउंटी में एक-एक मौत की खबर है।

एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने शुरू में पांच मौतों की खबर दी थी, जिसके बाद राज्य के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने शनिवार को बाद में छठी मौत की पुष्टि की। अधिकारियों ने कहा कि तूफान 11 अगस्त को इंडियाना से टकराना शुरू हुआ था।

लगातार हुई मूसलाधार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और कई सड़कें तथा रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। आपातकालीन सेवाओं को प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चलाना पड़ा। बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

इंडियाना के गवर्नर माइक ब्राउन ने शुक्रवार को प्रेसिडेंट इमरजेंसी की घोषणा की। शनिवार को, उन्होंने एक बयान जारी कर बताया कि संघीय सरकार ने मदद का वादा किया है। रिपब्लिकन ब्राउन ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'मैंने आज राष्ट्रपति ट्रंप से इंडियाना में आए भयंकर तूफान और बाढ़ के बारे में बात की, और उन्होंने कहा कि वह प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी घोषणा के हमारे अनुरोध को मंजूर करते हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मदद का वादा किया जिसकी हमें जरूरत है।' अधिकारियों के मुताबिक, कुछ इलाकों में दो दिनों के दौरान 11 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई।

किम जोंग-उन को रूस के साथ रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद, पुतिन को भेजा संदेश

» सोल, यूटर्न/ 16 अगस्त ।

उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन रूस के साथ अपने संबंधों को लेकर काफी पॉजिटिव हैं। उन्हें उम्मीद है कि दोनों देशों के रिश्ते आने वाले समय में और बेहतर होंगे। किम ने यह बात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भेजे एक संदेश में कही है। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने रविवार को इसकी जानकारी दी। योनहाप न्यूज एजेंसी के अनुसार, यह संदेश कोरिया की जापानी औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की 81वीं वर्षगांठ के मौके पर पुतिन की ओर से भेजे गए बधाई संदेश के जवाब में दिया गया। उत्तर कोरिया के सरकारी समाचार माध्यम केसीएनए ने बताया कि, किम ने शनिवार को भेजे अपने संदेश में रूस-उत्तर कोरिया संबंधों को साझा संघर्ष और दोस्ती की परंपरा पर आधारित बताया। किम ने कहा कि वह पुतिन के साथ मिलकर दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने में सक्षम होने पर गर्व महसूस करते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच मौजूदा साझेदारी भविष्य में और मजबूत होगी तथा आपसी सहयोग का दायरा बढ़ेगा।

किम और पुतिन के बीच पिछले कुछ वर्षों में रिश्ते तेजी से मजबूत हुए हैं। जून 2024 में पुतिन की प्योंगयांग यात्रा के दौरान दोनों देशों ने

व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में दोनों देशों के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने का प्रावधान भी शामिल है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और उत्तर कोरिया की नजदीकी और बढ़ी है। पश्चिमी देशों और दक्षिण कोरिया के अनुसार, प्योंगयांग ने रूस को हथियार और गोला-बारूद उपलब्ध कराया है। यही नहीं रूसी सेना की मदद के लिए सैनिक भी भेजे हैं। इसके बदले उत्तर कोरिया को रूस से सैन्य और तकनीकी सहयोग मिलने की आशंका जताई जाती रही है। पुतिन ने भी अपने संदेश में दोनों देशों के बीच सहयोग को रेखांकित किया। उन्होंने रूस और उत्तर कोरिया के संबंधों को ऐतिहासिक मित्रता से जोड़ते हुए कहा कि दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं और क्षेत्रीय सुरक्षा एवं स्थिरता के लिए समन्वय कर रहे हैं।

Owner, Publisher, Printer: - Komal Sharma, C/O Ummpl Marketing Pvt. 194-G, Sector 63, Noida 201307, Editor: Sandeep Sharma
Contact - +91 9888200619

* तमाम प्रकाशित सामग्री के चयन व संपादन हेतु आर.बी.एक्ट. के तहत जिम्मेवार *